साप्ताहिक
# शांति मिशन
नई दिल्ली

वर्ष-28 अंक- 23 06 - 12 जून 2021 पृष्ठ 12

अन्दर पढ़िए

नए शिक्षा मॉडल के दूरगामी प्रभाव पृष्ठ-6

ज़हरीला होता भूजल एक अहम मुद्दा पृष्ठ-7

# भारत में सांप्रदायिकता का जुनून अपने चरम पर

## मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना

### विश्व में कोई भी ऐसा धर्म नहीं है, जो अवसरवादिता और नफ़रत का संदेश देता हो, हर मज़हब विशेषकर ''इस्लाम'' मानवता की तालीम देता है।

पिछले दिनों केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल के विधायक भाई जालम सिंह को नकली रेमेडीसीवर इंजेक्शन लगा दिया गया। पुलिस ने जब इस गैंग के कुछ लोगों को पकड़ा तो पता चला कि उन्हें यह इंजेक्शन मध्य प्रदेश के मंत्री की पत्नी के ड्राइवर से मिले थे।

इस गैंग का दूसरा सदस्य वहां के मुख्य चिकित्साधिकारी का ड्राइवर था। आगे पुलिस जांच ठप पड़ गई, क्योंकि आपदा में अवसर तलाशते इन ड्राइवरों को नकली इंजेक्शन की आपूर्ति बड़े स्तर से हो रही थी। मेरठ में कफन चोरी करने वाला गैंग पकड़ा गया, तो उन्हें बचाने के लिए सत्तारुढ़ दल के एक ज़िलाध्यक्ष ने चिट्ठी लिखकर कहा कि ये अपने लोग हैं, मदद करें। जब लाखों लोग दवाओं के इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे थे, तब ये मौक़ापरस्त एक ऑक्सीजन सिलेंडर 30 से 50 हजार तक में बेच रहे थे। रेमेडीसीवर इंजेक्शन का भी यही हाल है। एक मित्र की बहन के लिए गाज़ियाबाद में यह इंजेक्शन 35 हज़ार का ख़रीदा गया। वह असली था या नकली नहीं पता, मगर बहन नहीं बच सकीं।

पैरासिटामोल हो या फिर ब्लैक फंगस की दवा, सभी धीरे-धीरे बाजार से गायब हो गई। अवसरवादी उन्हें मनमाने दामों पर बेचकर मुनाफा कमाते दिखे। किसी सरकार को क्या दोष दें, जब हमारे बीच के लोग ही यूं निकलें। कोरोना महामारी काल में जहां लोगों के रोज़गार छीन रहे हैं। बीमारी से लड़ने में तमाम लोगों के ज़ेवरात और ज़मीन बिक रही है। वहीं, कुछ पूंजीपतियों की आय और संपत्ति दोनों में दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है। अवसरवादी लोग एक दूसरों को लूटने लगे हैं। उस दौर में देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, महामारी से अधिक अपने नेता की छवि बनाने में लगे हैं। उन्होंने टवीट किया, 'कोरोना काल में भी पीएम नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था मज़बूत बनी हुई है।'

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 14 मई 2021 को समाप्त सप्ताह में 56.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 590. 028 अरब डॉलर हो गया। यह इस बात का संकेत है कि हमारी आर्थिक नीतियां सही दिशा में है।' देशवासियों को सेहतमंद रखने के लिए ज़िम्मेदार मंत्रालय के प्रमुख डॉ. हर्षवर्धन, यह नहीं बताते कि बग़ैर जांच, इलाज और ख़राब वित्तीय हालत के चलते दो माह में ही छह लाख से अधिक लोगों ने दम तोड़ दिया। सरकारी आंकड़ों में तीन लाख कोरोना मरीज़ों ने भी दम तोड़ा है। दो माह में सवा करोड़ लोग बेरोज़गार हो गये हैं। कोरोना काल में 10 करोड़ से अधिक लोग बेरोज़गारी और ग़रीबी की भेंट चढ़ गये। टीका के प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री का फोटो लगाने वाले उनके मंत्रालय ने राज्यों के हिस्सों का स्वास्थ्य बजट खुद ही ख़र्च कर लिया है।

युवाओं को बचाने के लिए केन्द्र सरकार के पास अब न बजट है और न वैक्सीन। राज्य सरकारें और युवा दोनों लाचार दिख रहे हैं। वैक्सीन बनाने पर एक भी रुपया ख़र्च न करने वाली हमारी सरकार आपदा में अवसर तलाशती रही। उसने प्रचार के बूते छवि बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब सरकार के पास इतना धन था, तब भी, उसने, उसे कुर्सी पर बैठाने वाली जनता को कोई राहत नहीं दी। सत्ता रईशी में जी रही है। उसके लिए राजमहल भी बन रहा है और राज दरबार भी। सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा में रोज़ाना पौने दो करोड़ रुपये और प्रचार में पर तीन करोड़ रुपये से अधिक ख़र्च होते हैं। विश्व की सबसे महंगी गाड़ियां और प्लेन उनके काफ़िले में हैं। अन्य ख़र्च भी रोज़ाना एक करोड़ रुपये से अधिक है।

देशवासियों की आय लगातार प्रतिव्यक्ति गिर रही है। रईस और भी रईस हो रहे हैं। ग़रीब और मध्य वर्ग आत्महत्या की ओर बढ़ चले हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि कोरोना काल में आत्महत्याओं में 30 प्रतिशत का इज़ाफ़ा हुआ है। इसमें सबसे अधिक किशोर और युवा 50 प्रतिशत हैं। जब देश को सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी मिले थे, तो उम्मीद जगी थी। उन्होंने युवाओं के भविष्य को सशक्त बनाने के लिए कम्प्यूटर और आईटी क्रांति के साथ ही युवा कार्यक्रमों को संचालित किया था।

यह राजीव गांधी जी के प्रयासों का ही नतीजा था कि 2014 का लोकसभा चुनाव आईटी और औद्योगिक क्रांति के बूते लड़ा गया। आईटी सेक्टर के साथ ही अन्य उद्योग इतनी तेजी से आगे बढ़े थे, जिससे योग्य युवाओं के आगे रोज़गार की लाइन लगी थी। अब वही युवा भिखारी की तरह झोली फैलाये खड़ है। टीका बनाने वाली हमारी तीनों सरकारी कंपनियों से काम नहीं लिया गया, जिससे युवाओं का वैक्सिनेशन कार्यक्रम टीके के अभाव में रुका हुआ है, जबकि इस बार मरने वालों में युवा सबसे ज़्यादा हैं। आपदा में अवसर तलाशने वालों ने युवाओं में रोज़गार की उम्मीद जगाने वाले दो दर्जन सार्वजनिक उद्यम बेच दिये। 224 बैंक शाखायें बंद कर दी गई। बेरोज़गार और फिर आर्थिक तंगी ने युवाओं को मानसिक रूप से विकृत करने का काम किया है। विदेशी और देशी मुद्रा भंडारण का रिकॉर्ड बताने वाली सरकार मौत के आंकड़े छिपाने में लगी है। हर राज्य में मौत के आंकड़े 400 से 500 प्रतिशत तक कम दिखाये जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के शिक्षक संघ ने 1621 शिक्षकों की पंचायत चुनाव में डयूटी के दौरान संक्रमित होने से मृत्यु का विवरण सरकार को सौंपा,

## भारत में अगले वर्ष सिंगल शॉट वैक्सीन लॉंच कर सकती है मॉडर्ना

मॉडर्ना का कोविड-19 एक खुराक वाला टीका अगले वर्ष भारत में उपलबध हो सकता है। इसके लिए वह सिप्ला तथा अन्य भारतीय दवा कंपनियों से बातचीत कर रही है। अमेरिका की ही फाइजर 2021 में पांच करोड़ टीके उपलब्ध कराने को तैयार है लेकिन वह क्षतिपूर्ति सहित कुछ नियामकीय शर्तो में बड़ी छूट चाहती है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। बातचीत की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि मॉडर्ना ने भारतीय अफसरों को यह बताया है कि उसके पास 2021 में अमेरिका से बाहर के लिए टीके का स्टॉक नहीं है। जॉनसन एंड जॉनसन भी निकट भविष्य में अमेरिका से अपने टीके को दूसरे देशों को भेज पायेगी इसकी भी बहुत सीमित संभावनायें हैं।

वैश्विक और घरेलू बाजारों में टीके की उपलब्धता को लेकर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में पिछले दिनों दो बार उच्चस्तरीय बैठकें हो चुकी हैं। इनमें विदेश मंत्रालय, नीति आयोग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, क़ानून मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी मौजूद थे। देश में कोविड-19 प्रतिरक्षण टीकाकरण अभियान में फिलहाल दो टीको कोविडशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है।

### मॉडर्ना का टीका बच्चों पर भी प्रभावी

माडर्ना ने दावा किया कि उसका कोविड-19 रोधी टीका वयस्कों के साथ ही उन बच्चों पर भी प्रभावी है जो 12 साल के हो चुके हैं। अमेरिका और कनाडा ने दो अन्य टीकों (फाइजर और बायोएनटेक द्वारा निर्मित) को 12 वर्ष के आयु वर्ग से ज़्यादा की उम्र के बच्चों को देनें की मंज़ूरी दी थी। मॉडर्ना को अभी यह मंज़ूरी मिलनी बाकी हैं उसने कहा कि वह जल्द अपने आंकड़े संबंधित विभागों को सौंपेगी।

# अफ़ग़ानिस्तान में शान्ति दूर की कौड़ी

अफ़गान शांति वार्ता की शुरुआत पिछले वर्ष सितम्बर में दोहा में हुई थी। इस वार्ता के नतीजे अभी तक कोई उत्साहजनक नहीं रहे हैं। शांति वार्ता में शामिल पक्षों के बीच आज भी विश्वास की कमी नज़र आ रही है। कोई भी पक्ष लचीला रुख़ नहीं दिखा रहा है। बातचीत जहां से शुरू हुई थी, लगभग वहीं पर है। ऐसे में वार्ता में प्रगति की कल्पना करना बेमानी है। पिछले दिनों तालिबान और अफ़गान सरकार के प्रतिनिधि फिर से दोहा में मिले। वार्ता शुरू हुई है। लेकिन इसका क्या नतीजा निकलेगा यह किसी को समझ नहीं आ रहा।

अफ़ग़ानिस्तान की निर्वाचित सरकार और तालिबान के बीच सबसे बड़ा विवाद सत्ता में भागीदारी को लेकर बना हुआ है। वर्तमान में अफ़ग़ानिस्तान पर शासन कर रहे राष्ट्रपति अशरफ़ ग़नी और उनके समर्थक किसी भी क़ीमत पर तालिबान का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वहीं, तालिबान भी ग़नी और उनके समर्थकों के नेतृत्व को नहीं मान रहा। ऐसे में अफ़ग़ानिस्तान का अगला राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा कैसा होगा, सरकार कैसी होगी, इस पर सहमति बनने के आसार दिख नहीं रहे हैं हालांकि इस दौरान दोनों पक्षों के सामने तीन तरह के प्रस्ताव आए। एक प्रस्ताव यह कि मौजूदा सरकार के नेतृत्व में तालिबान सत्ता में शामिल हो जाए। दूसरा प्रस्ताव यह कि तालिबान के नेतृत्व में सरकार बने, जिसमें वर्तमान सरकार शामिल हो जाए, तीसरा प्रस्ताव यह कि एक अंतरिम सरकार बनाई जाए। लेकिन राष्ट्रपति अशरफ़ ग़नी इन प्रस्तावों पर राज़ी नहीं हुए। बताया जाता है कि ग़नी चुनाव के लिए राज़ी हैं जिसमें आम जनता वोट देकर नई सरकार चुने। हालांकि तालिबान अंतरिम सरकार के गठन के प्रस्ताव पर राज़ी हैं, लेकिन वह सरकार में शामिल होने को तैयार नहीं है।

दोहा में जारी बातचीत को लेकर न तो तालिबान को बहुत उम्मीदें हैं, न अफ़ग़ान सरकर को। बीते छह माह में कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन सब बेनतीजा रही। बहुत से लोग इसके लिए अशरफ़ ग़नी को ज़िम्मेवार ठहरा रहे हैं, तो एक वर्ग हल नहीं निकालने के लिए तालिबान को ज़िम्मेदार बता रहा है। तालिबान अफ़ग़ानिस्तान में पूरी तरह से इस्लामिक व्यवस्था वाला शासन चाहता है।

अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफ़ग़ानिस्तान में आत्मघाती हमलों में अचानक तेजी आई है। तालिबान का यह आक्रामक रुख़ संदेह पैदा करने वाला है। वह शांतिवार्ता भी कर रहा है और साथ ही अफ़ग़ानिस्तान में लगातार हमले भी कर रहा है। एक और वह पाकिस्तान से भी सलाह-मश्विरा कर रहा है, तो दूसरी ओर वह ईरान व रूस के साथ भी संपर्क में है। बीते दिनों तालिबान के कुछ वरिष्ठ कमांडरों ने रणनीति बनाने के लिए पाकिस्तान में अपने कमांडरों

बाक़ी पेज 11 पर

## युद्ध अपराध के दायरे में आ सकते हैं गाज़ा में इज़राइली हमले

संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार प्रमुख ने कहा कि हमास शासित गाजा पट्टी में 11 दिन तक चले युद्ध में, हो सकता है कि इजराइली सैन्य बलों ने युद्ध अपराधों को अंजाम दिया हो। इजराइल से सैन्य कार्रवाई के लिए एक स्वतंत्र जांच कराने की अनुमति भी देने को कहा गया है। मिशेल बैचलेट की यह टिप्पणी तब आई है जब संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवाधिकार निकाय ने इस जंग में फलस्तीनियों की दुर्दशा पर चर्चा के लिए एक दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि संघर्ष के दौरान हमास की ओर से अंधाधुंध रॉकेट दाग़ना भी युद्धनियमों का स्पष्ट उल्लंघन था। मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र की उच्चायुक्त ने मानवाधिकार परिषद में 2014 के बाद से शत्रुता के अत्यधिक बढ़ने के घटनाक्रम का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया। इस संघर्ष में गाज़ा पट्टी में बड़े पैमाने पर बर्बादी व मौत हुई। दोनों पक्षों के बीच 11 दिनों तक चले संघर्ष में गाजा में 66 बच्चों और 39 महिलाओं समेत 248 लोगों की मौत हो गई। वहीं, इजरायल में भी दो बच्चे समेत 12 लोगों ने जान गंवाई। उन्होंने कहा, 'ऐसे घनी आबादी वाले इलाकों में हवाई हमलों से आम नागरिक बड़ी संख्या में हताहत हुए, साथ ही असैन्य आधारभूत ढांचे की बड़े पैमाने पर तबाही हुई।' बैचलेट ने कहा कि अगर नागरिकों पर इस तरह की कार्रवाई होती है तो 'ऐसे हमले युद्ध अपराध के दायरे में आएंगे।' ऐसी स्थिति में उन्होंने इजरायल से जवाबदेही सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पारदर्शी, निष्पक्ष जांच कराने कहा। उन्होंने कहा घनी आबादी वाले नागरिक इलाकों में सैन्य पहुंच का पता लगाना या उनसे हमले शुरू करवाना अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन है।



# ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत मामले में 5 लाख तक मिलेगा मुआवज़ा

ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई कोरोना मरीज़ों की मौत के मामले में परिजनों को अधिकतम 5 लाख तक का मुआवज़ा मिलेगा। इसके लिए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने 6 सदस्यीय कमेटी गठित की है।

कमेटी ऑनलाइन व ऑफ लाइन दोनों तरीकों से आवेदन व शिकायतें स्वीकार करेगी। कमेटी हर मामले की अलग-अलग मूल्यांकन कर मुआवज़े का मानदंड तय करेगी, जिसके आधार पर अधिकतम 5 लाख मुआवज़ा मिल सकेगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस कमेटी के सदस्य सप्ताह में दो बार व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर या वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से बैठक करेंगे, ताकि पीड़ित परिवार के आवेदन पर मुआवज़े का फैसला जल्द हो सके। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने कमेटी को हर सप्ताह विभाग के प्रधान सचिव को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। कमेटी प्राप्त आवेदन व शिकायतों के आधार पर संबंधित अस्पतालों से ऑक्सीजन आपूर्ति, ऑक्सीजन भंडारण की व्यवस्था और स्टॉक से संबंधित रिकॉर्ड तलब कर सकती है।

स्वास्थ्य विभाग ने कमेटी को अधिकार दिया है कि ज़रूरत महसूस होने पर कमेटी अस्पताल से कोई भी रिकॉर्ड मांग सकती है। अस्पताल में ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया था या नहीं ऑक्सीजन स्टॉक में है कि नहीं कमेटी पड़ताल करेगी।

कमेटी के सदस्यों में 1. डॉ॰ नरेश कुमार, निदेश प्रोफेसर, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, 2. डॉ॰ अमित कोहली एनेस्थिसिया विशेषज्ञ, लोकनायक अस्पताल, 3. डॉ॰ संजीव कुमार, एनेस्थिसिया विशेषज्ञ, एलबीएस अस्पताल, 4. सुरेंद्र कुमार, सहायक निदेशक (प्लानिंग), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, 5. डॉ॰ एन॰सी॰ शुक्ला, चिकित्सा अधीक्षक, माता चानन देवी, 6. डॉ॰ जे.पी. सिंह, चिकित्सा अधीक्षक, तीरथ राम अस्पताल। ❑❑

## दिल्ली : कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए विशेष दल गठित

कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बचाने के लिए दिल्ली में एक विशेष दल तैयार किया गया है। इस दल की सीधी निगरानी वरिष्ठ आइएएस अधिकारी सत्य गोपाल करेंगे और इस टीम में कुल 13 सदस्य शामिल होंगे। इस बाबत दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव अमित सिंघला ने आदेश जारी किए हैं। ये आदेश उपराज्यपाल की मंज़ूरी के बाद जारी किए गए है।

आदेशों के मुताबिक इस व्यवस्था से अस्पतालों में कर्मचारी, डॉक्टर, आइसीयू बिस्तर व अन्य उपकरण समेत अन्य सेवाओं को सुनिश्चित करने में यह टीम मददगार साबित होगी। व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो। इसके लिए स्वास्थ्य सचिव डॉ. आशीष चंद्रा, मंडलायुक्त संजीव खिरवाल भी इस टीम में जोड़े गए हैं। ये सभी नोडल अधिकारी दिल्ली की सभी सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए तैनात रहेंगे। इनके पास अस्पताल प्रबंधन, ऑक्सीजन की व्यवस्था, दवा आपूर्ति आदि की व्यवस्थाएं रहेंगी।

इस टीम का काम केवल स्वास्थ्य सेवाओं की अन्य आवश्यक चीजों के प्रबंधन से भी जुड़ा रहेगा ताकि किसी भी प्रकार की कमी से लोगों को नहीं जूझना पड़े। इससे पहली लहर में आम जनता को पहली बार ऑक्सीजन व ऑक्सीजन सिलेंडर आदि तक के लिए लाइनों में लगना पड़ा था। संकट यह भी था कि इन सामान को किस प्रकार तक अस्पतालों तक पहुंचाया जाए। इस बार आदेशों में परिवहन व्यवस्था का प्रबंधन भी दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया है ताकि आपातकालीन स्थिति में किसी भी प्रकार की कोई असमंजस की स्थिति पैदा नहीं हो। यह टीम कम से कम आपात स्थिति के लिए 10 हज़ार कुशल पैरामेडिकल स्टाफ का भी प्रबंधन करेगी और इस व्यवस्था से सिविल डिफेंस को भी जोड़ा जाएगा ताकि आपदा प्रबंधन में आम जनता को कोई परेशानी नहीं हो। इन आदेशों की प्रति सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को भेजी गई है।

# इतिहास से सबक़ लिया जाता है गर्व नहीं किया जाता

इतिहास बहुत विचित्र होता हैं उसमें बहुत से अगर-मगर होते हैं। किन्तु उसकी गति को पकड़ना सहज नहीं है। न उस पर गर्व कर सकते हैं न उसे किनारे लगा सकते हैं। वह हमारे सामने सदैव खड़ा रहेगा। एक अच्छा शासक वह है, जो इतिहास से कुछ सीखता है। कोई भी इतिहास तब प्रेरणा देगा, जब उसके प्रति हम एक वैज्ञानिक रवैया अपना कर उसे पढ़ें। न तो उस पर गर्व करें न शर्म। भारतीय शासकों की दिक्क़त यह है कि या तो वे उस पर गर्व करते हैं अथवा शर्म और इसी वजह से किसी भी संकट के आने पर उनके हाथ-पैर फूल जाते हैं क्योंकि गर्व या शर्म उन्मादी भाव है इनमें किसी भी तरह की सापेक्ष इतिहास दृष्टि नहीं है। अगर आज की मोदी सरकार 1918 के स्पेनिश फ्लू के सम को समझ लेती तो यह नौबत न आती जो आज दिख रही है। कुल सौ वर्ष पहले जो महामारी आई थी, उसके सबक़ याद रखने थे और सीख लेनी चाहिए थी कि आख़िर क्या वजह थी कि उस महामारी में करीब 5 करोड़ लोग मारे गए थे। इसके बाद प्लेग व चेचक जैसी महामारियां फैलीं और उनसे निजात पाया गया। यह तो कोई तर्क नहीं हुआ कि भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए अफरा-तफरी फैली। आबादी तो चीन की हमसे भी अधिक है, उन्होंने कैसे क़ाबू पाया? इन सब बातों पर ग़ौर करना था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भावनाओं के जिस रथ पर सवार होकर आए थे, उससे उनके चाहने वालों ने मान लिया कि यही असली हिन्दू हृदय सम्राट है। किन्तु इन स्व-घोषित हिन्दू हृदय सम्राट को कभी भी हिन्दू शासकों से ही सबक़ नहीं ले पाए। देश की दो बड़ी हिन्दू रियासतें - कच्छ और मणिपुर, विदेशी हमलों के समय भी तन कर खड़ी रहीं। लेकिन उनके शासकों ने कैसे महामारियों का सामना किया, यह ग़ौर करने वाली बात है। दोनों छोटी और बियाबान में आबाद रियासतें रहीं। लेकिन रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण। एक सुदूर पश्चिम में अरब सागर के तट पर नमक के रेगिस्तान में खड़ी रहकर भारत पर होने वाले हमलों को झेलती थी दूसरा राज्य उत्तर पूर्व के मैदानों से। एक बार 1819 में कच्छ में 7.2 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया और पूरा कच्छ बर्बाद हो गया।

कच्छ के महाराजा ने अपने वज़ीर फतेह मोहम्मद को कहा कि कच्छ को फिर से खड़ा करो। एक साल के अंदर ही तबाह हो चुका कच्छ दोबारा पहले के ही तरह खड़ा हो गया। वहां के सौदागर फिर से अरब और अफ्रीकी के जांबिया तक अपने जहाज भेजने लगे। इसी तरह 1918 में जब स्पैनिश फ्लू फैला तो मणिपुर के बालक महाराजा चूड़चंद्र सिंह ने सफलतापूर्वक इसे फैलने से रोका था। अब देखिए, इन मोदी सम्राट को, जो कोविड का सामना बस ताली और थाली बजवा कर करते रहे। ऐसे में लोग अगर बच रहे है तो अपने भाग्य से। सरकार का उसमें कोई इक़बाल नहीं हैं अंग्रेज जब भारत आए तब हिन्दुस्तान में मुग़ल वंश का सूर्य अस्त हो रहा था। बादशाह आलमगीर औरंगज़ेब ने ही मुग़ल सल्तनत को अटक से कटक तक और कश्मीर से सुदूर दक्षिण तक फैला दिया था किन्तु आग जितनी फैलती है, उतने ही अधिक अपने शत्रु पैदा करती है।

अपना साम्राज्य बढ़ाने के चक्कर में औरंगज़ेब ऐन आगरा के आसपास न देख सका, जहां जाट विद्रोह कर रहे थे और न ही पंजाब को जहां के सिख स्वतंत्र होने के लिए कसमसा रहे थे। ऊपर से मराठा आग की तरह पूरे देश में फैलने को व्यग्र थे। इसके अलावा अफग़ान और पठान भी स्वतंत्र रियासतें क़ायम करने को आतुर थे। उधर पुर्तगालियों और डच के बाद अब फ्रेंच व अंग्रेज भी हिन्दुस्तान को बाज़ार बनाना चाहते थे। यह मौक़ा मिला 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी की लड़ाई में हरा दिया और एक संधि के तहत बंगाल की दीवानी अपने हाथों में ले ली। तब तक मुग़ल बादशाह बहुत कमज़ोर हो गए थे। औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी। इस बीच दिल्ली की गद्दी पर जो भी बैठा वह नाम का ही शासक था। जब प्लासी का युद्ध हुआ दिल्ली का बादशाह शाहजहां तृतीय था लेकिन तब तक अंग्रेज दिल्ली बचते रहे। इसके बाद मराठे, अफग़ान तथा पठान बढ़ने लगे।

1760 में शाहजहां तृतीय की मौत के बाद शाहआलम गद्दी पर बैठा, जो कठपुतली शासक ही रहा। इस बीच ईरान के शासक नादिर शाह दिल्ली में क़त्ल-ए-आम कर चुका था। अहमदशाह अब्दली भी कई बार दिल्ली को लूट चुका था। मगर हिन्दुस्तान का बादशाह मराठों, सिक्खों, अफग़ान पठानों से घिरा हुआ था। इनमें सबसे अधिक शक्तिशाली थे मराठे, जो सुदूर तमिलनाडू के तंजोर से लेकर लाहौर और फिर पूरब में अवध तक चले आते। मगर ये मराठे 14 जनवरी 1761 में पानीपत की लड़ाई में हार गए। अफ़ग़ानिस्तान के दुरानी शासक अहमद शाह अब्दाली ने इस लड़ाई में मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ को हरा दिया। इस युद्ध में पतनकी दास्ताँ लिख दी। अंग्रेज़ यह देख रहे थे और प्लासी युद्ध के सात वर्ष बाद उन्होंने 1764 में बक्सर की लड़ाई छेड़ दी। इसमें बंगाल के नवाब मीर क़ासिम, अवध के नवाज शुजाउद्दौला तथा बादशाह शाह आलम द्वितीय और काशी के राजा बलवंत सिंह की सम्मिलित सेनाएं थीं। लड़ाई में अंग्रेज़ों की जीत हुई। अंग्रेज़ों ने बादशाह शाह आलम को पकड़ लिया। यह हिन्दुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा कलंक था क्योंकि कुछ भी हिन्दुस्तान के बादशाह की एक प्रतीकात्मक इज़्ज़त थी। किन्तु मराठों की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि वे बादशाह को छुड़ा सकें।

नतीजा यह हुआ कि बंगाल के बाद अब ओडिशा, बिहार की दीवानी भी अंग्रेज़ों को देनी पड़ी तथा इलाहाबाद और कड़ा जहानाबाद का 40 हज़ार वर्ग किमी का इलाक़ा भी। इसके बाद क्या हुआ, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है लेकिन यहां तक कि सारी घटनाएं इस बात की गवाही देती हैं कि इस देश के इतिहास में सत्ता की लड़ाईयां तो थीं, परंतु इसमें धार्मिक उन्माद या धर्म के तौर पर एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना न रहती, वर्ना मराठे पेशवाओं और अहमदशाह अब्दाली के साथ युद्ध में इब्राहीम गार्दी पेशवा की ओर से लड़ता न सिख योद्धा अब्दाली को रसद भिजवाते। यह सबक़ सीखना था। मगर सबक़ यह लिया गया कि औरंगज़ेब धर्मांध था अथवा पेशवाओं को हरवाया गया क्योंकि दिल्ली दरबार यह चाहता था। इस तरह की बातें एक समाज को नीचे की ओर धकेलती हैं। जहां विज्ञान नहीं होता, समाज को आगे की ओर ले जाने की ललक नहीं होती।

धर्म पर थोथा दंभ किया जाता है। इसे सबसे पहले गांधी जी ने समझा था, कि इस देश को समूचा बनाए रखना है तो सबसे पहले अंग्रेज़ों की विभाजनकारी नीतियों काा जवाब देना होगा और हमें अपनी कमियां दूर करनी होंगी। अस्पृश्यता निवारण या ख़िलाफत आंदोलन को समर्थन देने के कारण बार-बार बहुसंख्यक हिन्दुओं के विरोध को उन्होंने झेला पर डटे रहे। बहुसंख्यकों के विरोध के बावजूद वे सबके निर्विवाद नेता बने रहे। इसी तरह नेहरू जी ने भी कई बार झुक कर समझौते किए, क्योंकि वह उस वक्त देश को बचाने के लिए आवश्यक था।

उन्होंने वे नीतियां अपनाईं, जिसके चलते वे अक्सर हिन्दू विरोधी नज़र आते हैं किन्तु कई बार किसी समाज के हित के लिए उसका विरोध झेलना पड़ता है। नेहरू जी ने महामारियों के लिए वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति पर ज़ोर दिया और इतिहास से यह सीखा कि दिखने में बड़ा देश दिखते हुए भी यह देश बहुत कमज़ोर था। सबको साधने के लिए कई बार आपको लोकधारा के विरुद्ध आचरण करने पड़ते हैं, नरेन्द्र मोदी में यह साहस होता तो वे अपने हिन्दू इतिहास से ही सबक़ ले लेते।□□

## तारीख़े इस्लाम
# ख़ुतबाते सीरते तैयिबा
**मुफ़्ती मुहम्मद सलमान मंसूरपुरी** किस्त-76

चुनान्चे अबू सुफ़ियान की सरकरदगी में एक बड़ा लश्करे जर्रार तीन हज़ार अफ़राद पर तैयार हुआ और मक्का मुअज़्ज़मा से शव्वाल 3 हिजरी में मदीने पर चढ़ाई के इरादे से यह लश्कर चला, हज़रत अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हु जो पैग़म्बर अलैहिस्सलाम के चचा थे, और मक्का मुअज़्ज़मा में मुक़ीम थे, इस्लाम ला चुके थे, मगर इस्लाम ज़ाहिर नहीं फ़रमाते थे, उन्होंने हालात का जायज़ा लेकर पैग़म्बर अलैहिस्सलाम को ख़त लिखा कि इस इरादे से कुफ़्फ़ार मक्का से रवाना हो चुके हैं, उस वक़्त मक्का से मदीना तक पैदल का रास्ता तक़रीबन एक हफ़्ता का था, ख़त लाने वाले ने सिर्फ़ तीन दिन में पहुंचा दिया, नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम क़ुबा में तशरीफ़ रखते थे, आप को जैसे ही ख़बर मिली, तो आप ने अपने मुख़्लिस सहाबा को जमा फ़रमाया, और ख़बर दी कि इस तरह से मक्का के लोग मदीने पर हमले के लिए चल दिए हैं, और आप ने कुछ लोगों को इधर उधर भी भेजा, तो अंदाज़ा हुआ कि लश्कर क़रीब आ चुका है। चुनान्चे आप ने सहाबा से मशवरा किया, एक राय यह सामने आई कि हम लोगों को मदीने के अंदर रह कर लश्कर का मुक़ाबला करना चाहिये, क्योंकि यह बाहर का लश्कर है और मदीने के रास्तों और गलियों से वाक़िफ़ नहीं है, अगर यह अंदर आ जायेगा तो घेरने में सहूलत होगी, लेकिन वे हज़राते सहाबा जो ग़ज़्वा-ए-बद्र में नहीं जा सके थे, और उनके अंदर जिहाद का जोश व जज़्बा कुलबुला रहा था, उन्होंने यह राय दी कि नहीं बाहर निकल कर उसका मुक़ाबला करना चाहिये, पैग़म्बर अलैहिस्सलाम की राय अंदर रह कर ही मुक़ाबला करने की थी लेकिन जब आप ने यह देखा कि आम लोगों की राय यह बन रही है, तो आप घर में तशरीफ़ ले गए और आप ने हथियार वग़ैरह पहन कर अमामा बाँधा और बाहर तशरीफ़ लाए। (अर-रहीक़ुल मख़्तूम 389,391)

इस दौरान सहाबा में यह गुफ़्तुगू होने लगी कि हम ने हुज़ूर पर दबाव बना कर अच्छा नहीं किया, हमें यह कहना चाहिये था कि हज़रत आप जैसा चाहें वैसा करें, अंदर बाहर की बात हमें नहीं कहनी चाहिये थी, हुज़ूर जैसा फ़रमाते वह अच्छा होता। जब आप बाहर तशरीफ़ लाए तो सहाबा ने कहा कि हुज़ूर चूंकि आप ने मालूम किया था, इस लिए हम ने कह दिया वरना असल राय तो आप ही की है, पैग़म्बर अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि :''जब नबी हथियार पहन लेता है तो उस वक़्त तक नहीं उतारता जब तक कि फ़ैसला आर पार न हो जाए, इस लिए अब तो फ़ैसला हो चुका''। और मदीना मुनव्वरा से मुक़ाबले के लिए एक हज़ार अफ़राद चले।(असह-हुस-सियर 102)

आज तो मदीना मुनव्वरा माशा अल्लाह बहुत बड़ा हो गया है, और ओहुद पहाड़ भी ऐसा ही लगता है, जैसे वह मदीना ही के अंदर हो, आबादी मुसलसल बढ़ रही है, उस ज़माने में ''ओहुद'' बिल्कुल अलग था, और अब भी फ़ासला तो काफ़ी है लेकिन आबादी की वजह से पता नहीं चलता।

मुशरिकीन का लश्कर ओहुद पहाड़ के क़रीब जाकर ठहर गया, उस वक़्त में वहाँ का रास्ता ऐसा था कि उसी की जानिब से मदीने में दाख़िल हो सकते थे, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, अब तो बिल्कुल सूरत ही बदल गई इसका कोई अंदाज़ा लगाया ही नहीं जा सकता, चुनान्चे पैग़म्बर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले चले, तो रास्ते में अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल ने धोका बाज़ी की, जब बिल्कुल पड़ाव पर पहुंच गए, तो उस लईन ने कहा कि मुझे तो यहाँ अपने सामने मौत नज़र आ रही है, और मैं अपने को हलाकत में डालना नहीं चाहता, और 300 आदमियों को लेकर वापस हो गया।(असह-हुस-सियर पृष्ठ 102)

अब 1000 में से 300 कम होकर 700 बाक़ी रह गए, और उस ने न सिर्फ़ यह कि दग़ा दी बल्कि अंसार के कुछ क़बीलों को भी साथ ले जाने की कोशिश की, मगर अल्लाह तआला ने उनके दिलों को मज़बूत किया और ये हज़रात जंग के लिए तैयार और मुसतइद हो गए। (जारी)

# लड़ाई आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच नहीं है

## डॉ॰ जे॰ए॰ जयालाल

**कोरोना महामारी के बीच आईएमए बनाम बाबा रामदेव विवाद गरमा गया है। आरोप प्रत्यारोप ऐसे दौर में पहुंच गए हैं, जहां बहुतों को लग सकता है कि मामला कहीं आयुर्वेद और एलोपैथी का तो नहीं, दूसरी ओर महामारी भी रूप बदलकर सबकी चिंता बढ़ा रही है। विवाद और महामारी से जुड़े मसलों पर आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट डॉ. जे. ए. जयालाल से बातचीत हुई, पेश है, इस बातचीत के प्रमुख अंश :-**

**प्रश्न:-** बाबा रामदेव और आपकी संस्था के बीच पिछले कुछ दिनों से काफी सारी बातें चल रही हैं। आपका क्या कहना है.?

**उत्तर:-** एक ओर खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कह रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग वैक्सीन लगवाएं, दूसरी ओर बाबा रामदेव वैक्सीन के ख़िलाफ़ प्रचार कर रहे हैं। मुझे बताइए, क्या यह एंटी नेशनल नहीं है? बाबा रामदेव सीधे-सीधे देश के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। क्या उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा? हम इस बयान के ख़िलाफ़ अपने स्तर से लीगल एक्शन ले रहे हैं, बाकी आगे क्या होगा, यह देश का क़ानून तय करेगा।

**प्रश्न:-** तो क्या यह लड़ाई अब आयुर्वेद बनाम एलोपैथी की ओर बढ़ रही है?

**उत्तर:-** सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाबा रामदेव आयुर्वेद का चेहरा नहीं है। वे एक व्यापारी हैं, जो अपनी कंपनी चलाते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक चिकित्सा पर विवेकहीन बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये क्या बात हुई कि वह कंपनी का प्रचार करने के लिए बाकी सब लोगों पर आरोप लगाते रहेंगे? यह देश क़ानून से चलता है, आईएमए, स्वास्थ्य मंत्रालय आदि गाइडलाइन्स जारी करते हैं। हर दवा के पीछे नियम और क़ानून है। हम अपना काम कर रहे हैं। हमारी आयुर्वेद के साथ कोई लड़ाई नहीं है बल्कि हम तो आयुर्वे के साथ भी काम करने के लिए तैयार हैं। हम आयुर्वेद को क्रिटिसाइज नहीं करते, लेकिन ऐलोपैथी पर और वैज्ञानिक चिकित्सा पर बाबा रामदेव कुछ भी कहते रहें, यह कैसे हो सकता है?

**प्रश्न:-** सब कह रहे हैं कि पैन्डेमिक श्रिंक कर रहा है। क्या वाक़ई ऐसा हो रहा है या यह सिर्फ आंकड़ेबाज़ी है?

**उत्तर:-** रिकवरी रेट बढ़ा है, पर अभी भी संकट कम नहीं हुआ है। शहरों में फिर भी टेस्ट और वैक्सिनेशन अधिक संख्या में हो रहे हैं, लेकिन सरकार को अब ग्रामीण इलाकों की ओर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि वहां की स्वास्थ्य सेवाएं अव्यवस्थित है। लोगों में मूवमेंट अब भी जारी है। कुछ राज्यों में लॉकडाउन तो है, पर अधिकतर सेवाएं चल रही है। लोग एक राज्य से दूसरे राज्य आ जा रहे हैं। मूवमेंट की वजह से संक्रमण फैलने का ख़तरा लगातार बना हुआ है।

**प्रश्न:-** अब वैज्ञानिक तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, जिसमें बच्चों पर सबसे ज़्यादा ख़तरा बताया जा रहा है। आईएमए इसके लिए संगठन स्तर पर क्या कर रही है.?

**उत्तर:-** स्थिति से निपटने के लिए राज्यों का लॉकडाउन ही काफी नहीं है। हम सब मिलकर अधिक से अधिक वैक्सीन लग सके, इस पर काम कर रहे हैं। माना जाए तो इस महामारी से निपटने के लिए यह एक इकलौता रास्ता है। आईएमए कॉन्फिडेंट है कि देश तीसरी लहर फेस करने के लिए तैयार है। 18 से अधिक आयु के लोगों को जिस तेज़ी से वैक्सीन लगाई जा रही है, उससे यह कहा जा सकता है। बच्चों पर विशेष ध्यान देना होगा, मां-बाप को उन्हें बाहर आने जाने से बचाना होगा। जब तक ज़्यादा से लोगों के वैक्सीनेशन के बाद हर्ड इम्युनिटी विकसित नहीं हो जाती, तब तक हमें सावधान रहने की ज़रूरत है।

**प्रश्न:-** पिछले दिनों आईएमए ने कहा कि वैक्सिनेशन डोर-टू-डोर होना चाहिए। सरकार इसके लिए राज़ी नहीं दिख रही है। आपकी नज़र में क्या प्रॉब्लम हो सकती है..?

**उत्तर:-** हम बार-बार सरकार से मांग कर रहे हैं कि देश में जल्द से जल्द डोर-टू-डोर वैक्सिनेशन शुरू कर दिया जाए। हमने उसके लिए प्रधनमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को चिट्ठी भी लिखी। हम आश्वस्त हैं कि जल्द ही इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। यह दो स्टेप की प्रक्रिया है। पहला जो कि शहरों या बाकी जगहों पर अभी हो रहा है कि लोग जहां वैक्सीन मिल रही है, वहां पहुंच वैक्निेशन करा रहे हैं। दूसरा यह कि ग्रामीण इलाकों में जहां जागरुकता नहीं है, वहां ग्राम पंचायतों में या घर-घर जाकर वैक्सीन लगानी होगी। सरकार पहले स्टेप पर चल रही है। वैक्सिनेशन में सरकार को तेज़ी लानी होगी और बहुत जल्द 60 से 70 प्रतिशत वैक्सिनेशन के लक्ष्य को पूरा करना होगा। हमने सरकार से कोरोना वॉरियर्स के लिए मौजूदा बीमा योजना की अवधि 6 माह बढ़ाने की भी मांग की है और कहा है कि कोरोना के शिकार डॉक्टरों के परिवारों को तय राहत राशि मुहैया कराई जाए।

**प्रश्न:-** दोनों वैक्सीन लेने के बावजूद लोगों की मौत हो रही हैं हालांकि वैक्सीन लगने से सेफ रहने वालों के आंकड़े भी उत्साहजनक हैं, पर ये मामला क्या है..?

**उत्तर:-** मैं इससे इंकार नहीं करूंगा कि दोनों वैक्सीन लेने के बाद कुछ लोगों के मरने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में वैक्सीन की सफलता पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। लेकिन यहां मैं बता दूं कि वैक्सीन लगने के बाद 99.05 प्रतिशत लोग कोरोना से बच भी रहे हैं जो दूसरे केस आ रहे हैं, उनके कारणों पर लगातार शोध हो रहे हैं। अधिकतर में पाया जा रहा है कि उनमें पहले से कई बीमारियां हैं। वैक्सीन लगने के बाद संक्रमण में किसी मामले को निर्णायक तभी माना जाएगा, जब संक्रमण पूरी वैक्सीन लगने के दो सप्ताह बाद हुआ हो। ❑❑

## पंजाब में अकाली दल ने हमारी नैया डुबोई अब उससे गठबंधन का कोई प्रश्न ही नहीं : दुष्यंत गौतम

**प्रश्न:-** पंजाब में चुनाव को ज़्यादा वक़्त नहीं बचा है, आप वहां पार्टी का क्या भविष्य देख रहे हैं?

**उत्तर:-** पंजाब के लोग सबको आज़मा चुके हैं। कांग्रेस को भी, अकाली दल को भी। वहां हमारी पार्टी बेहतर विकल्प के रूप में खड़ी है। वहां पर हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने की गुंजाइश है।

**प्रश्न:-** लेकिन पंजाब में तो आप अकाली दल के ही भरोसे रहा करते हैं। इस बार आपका सबसे पुराना सहयोगी साथ नहीं होगा..?

**उत्तर:-** अच्छा है कि साथ नहीं होगा। पिछले चुनाव में आपने देखा ही होगा, उन्होंने अपनी नैया डुबोई ही, हमारी भी डूबो दी। पब्लिक भाजपा से क़तई नाराज़ नहीं थी, लेकिन अकाली दल के साथ हमें उसका नुकसान उठाना पड़ गया। पंजाब के लोग अकाली दल से नाराज़ थे, कांग्रेस को भी लाना नहीं चाह रहे थे, इसी वजह से वहां आम आदमी पार्टी के लिए जगह बन गई। यूं समझ लीजिए अकाली दल से हमें फायदा कम हुआ, नुकसान ज़्यादा।

**प्रश्न:-** क्या ऐसी कोई संभावना है कि राज्य में कांग्रेस को रोकने के लिए अकाली दल और भाजपा फिर हाथ मिला लें?

**उत्तर:-** ऐसी कोई संभावना नहीं है। हम अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। सभी राज्य अब भाजपा और नरेन्द्र मोदी के साथ चलना चाहते हैं। जिन राज्यों में क्षेत्रीय दलों का अधिपत्य माना जाता रहा है, वहां भी वोटरों की पहली पसंद भाजपा बन रही है। महाराष्ट्र में अगर शिवसेना के लिए हमने सीटें नहीं छोड़ी होतीं, तो स्पष्ट बहुमत हमारा होता। बंगाल में हम सरकार नहीं बना पाए पर हमारी सीटें और वोट प्रतिशत देखिए। असम में हमने दोबारा जीत दर्ज की।

**प्रश्न:-** लेकिन पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल दोनों के पास मुख्यमंत्रियों के चेहरे हैं, जबकि भाजपा का कोई घोषित चेहरा नहीं है..?

**उत्तर:-** मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ा जाएगा या बग़ैर चेहरे के लड़ा जाएगा, यह फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। इसलिए मैं अभी से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना बता सकता हूं कि चेहरा घोषित करने या नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वोटर नरेन्द्र मोदी जी और भाजपा को वोट करता है, वह किसी चेहरे पर वोट नहीं करता।

**प्रश्न:-** पंजाब में इस समय कांग्रेस के अंदर बहुत उठापटक चल रही है। इसका क्या असर आप वहां की सियासत पर देखते हैं..?

**उत्तर:-** कांग्रेस में जो चल रहा

बाक़ी पेज 11 पर

## योग गुरु की बेतुकी बातें

योग गुरु बाबा रामदेव अपने बयानों के कारण हमेशा विवादों में बने रहे हैं। इस बार एलोपैथी के डॉक्टरों के ख़िलाफ़ दिए बयान के कारण रामदेव बुरी तरह फंस गए हैं। हर कोई उनकी निंदा कर रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की राष्ट्रीय इकाई और उत्तराखंड इकाई दोनों ने रामदेव के ख़िलाफ़ डटकर मोर्चा खोल दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड की इकाई ने तो उनके ख़िलाफ़ एक हज़ार करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करने के लिए क़ानूनन नोटिस भेज दिया। पन्द्रह दिन के भीतर रामदेव से माफी मांगने या नोटिस का जवाब देने की बात कही है। वरना एसोसिएशन मानहानि का दावा करेगी और उनके ख़िलाफ़ मुक़द्दमा दर्ज कराएगी। उधर रामदेव के ख़िलाफ़ केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को सख़्त शब्दों में चिट्ठी लिखनी पड़ी। उसके बाद स्वामी रामदेव ने माफी मांग ली थी। लेकिन रामदेव के सोशल मीडिया खाते पर एलोपैथी डॉक्टरों के ख़िलाफ़ अभद्र टिप्पणियां की गई जिससे मामला और गरमा गया। रामदेव के ख़िलाफ़ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कई आरोप लगाए जिससे उनका पक्ष मज़बूत होने के बजाए कमज़ोर हुआ। योग गुरु की बेतुकी बातों को पढ़े-लिखे समाज ने नकारा और उनकी छवि इस घटनाक्रम से ख़राब हुई। एलोपैथी के डॉक्टर सवाल कर रहे हैं कि जब 2011 में रामदेव दिल्ली के रामलीला मैदान में अपने धरने से एक महिला के कपड़े पहन कर और भागकर हरिद्वार अपने पतंजलि आश्रम आए थे और अनशन पर बैठे थे तब अनशन पर बैठने से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें जौलीग्रांट के हिमायल एलोपैथी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। तब एलोपैथी के डॉक्टरों ने ही उनकी जान बचाई थी और इसी तरह दो वर्ष पहले कथित फूड प्वाइजनिंग की घटना में जब उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण बेहोश हो गए थे तब उन्हें हरिद्वार के एलोपैथी हॉस्पिटल भूमा निकेतन में भर्ती कराया गया था। वहां तबीयत सुधरने के बाद उन्हें ऋषिकेश एम्स के एलोपैथी के डॉक्टरों ने उनकी जान बचाई थी और आज रामदेव को एलोपैथी के डॉक्टर और चिकितसा पद्धति बकवास लग रही है। जिस तरह से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रामदेव की घेराबंदी की है वे अलग थलग पड़ते दिखाई दे रहे हैं। जब कोरोना से बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं तब उन्होंने ऐसी बेतुकी बहस छेड़ी दी जो इस समय माहौल को और ख़राब कर गया। हालांकि विवाद को ज़्यादा तूल पकड़ते देख रामदेव ने माफी मांगते हुए कहा कि मैं बात को ख़त्म करते हुए माफी मांगता हूं।

# सेवा के दावे पर कितना भरोसा

कोरोना के दूसरे भयावह दौर में राजनीति में अभी चिट्ठियों का दौर चल रहा है, 'लेटर बम' भेजे जा रहे हैं। इंटरनेट, वाटस्ऐप्प, टवीटर और इंस्टाग्राम के साथ मोबाइल फोन के ज़माने में जब चिट्ठियां लिखना दूर की बात हो गई, तब राजनीतिक दलों को यह सबसे ताक़तवर हथियार लग रहा है। राजनीतिक दल अपने विरोधी नेता को चिट्ठि लिख रहे हैं। चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत देश के 12 विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री को चिट्ठि लिखी है और नौ सुझाव दिए हैं। उनमें बात सिर्फ कोरोना की नहीं है कुछ और भी राजनीतिक सुझाव है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रध ानमंत्री मोदी को चिट्ठि लिखी, तो उसका कड़ा सा जवाब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भेजा, फिर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लंबी चिट्ठि लिखी, तो उससे भी लंबा जवाब भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने भेज दिया। उत्तर प्रदेश में मंत्री और एमएलए मुख्यमंत्री को चिट्ठि लिख रहे हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हरेक दिन करीब चार लाख नए संक्रमित मरीज मिले और करीब चार हज़ार लोगों की प्रतिदिन मौत का आंकड़ा रहा। यह तो सरकारी आंकड़ा है, अनुमान इससे कई गुना ज़्यादा मौत होने का है, वरना गंगा, यमुना और दूसरी नदियों में लाशें बहती न दिखतीं और न ही श्मशानों व कब्रिस्तानों में मुर्दों के लिए जगह कम पड़ती।

इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि लोकतंत्र में सरकारों से प्रश्न पूछना ज़रूरी है और विपक्ष में बैठे राजनीतिक दलों के लिए यह सबसे मज़बूत हथियार है। प्रश्न है, क्या सबसे ज़रूरी काम इस वक्त प्रश्न पूछना भर है वह भी तब, जब एक राज्य में कोई पार्टी सरकार में है, तो दूसरी विपक्ष में और हर जगह हाल यही है कि अपने गिरेबान में झांकने के बजाय हर कोई दूसरे पर उंगली उठा रहा है। इस सबके बीच पीस रहा है आम आदमी, जिसके लिए अस्पताल में न बेड है, न ऑक्सीजन और न ही वेंटिलिटर और बिना इलाज के मर जाए, तो श्मशान-कब्रिस्तान में भी जगह नहीं है। जन-नाराज़गी से पीछा छुड़ाने के लिए 'पॉजिटिविटी अनलिमिटेड कैंपेन' शुरू कर दिया गया है, पर क्या सिर्फ भाषणों और प्रवचनों से पॉजिटिविटी आ सकती है?

केन्द्र और राज्यों में बैठी सरकारें तो अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही हैं, हैरानी है कि 'राष्ट्र को प्रथम' और 'समाजसेवा के लिए राजनीति में' आए हमारे राजनीतिक दल, उनके नेता और कार्यकर्ता भी इस समय कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वर्ष 1950 में लोकतंत्र को अपनाने वाले इस देश में आज करीब 2300 राजनीतिक दल हैं। इनमें चुनाव आयोग में सात राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर और 59 राज्य स्तरीय पार्टी के तौर पर पंजीकृत हैं। करीब 800 सांसद हैं, 4120 विधायक हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा भाजपा के 1300 और कांग्रेस के 870 विधायक है। इसके साथ ही हजारों की तादाद में पार्षद, पंच और सरपंच हैं। राजनीतिक दलों के सदस्यों की तादाद देखी जाए, तो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा के 18 करोड़ सदस्य है और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के 2 करोड़ सदस्य हैं सबसे बड़े सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक करोड़ से ज़्यादा स्वयंसेवक हैं। कुल मिलाकर, 30 करोड़ से ज़्यादा सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता देश में है, यानि औसतन हर परिवार के पीछे एक राजनीतिक कार्यकर्ता मिल सकता है और यदि देश के कुल ढाई करोड़ कोरोना मरीज़ों की तादाद मानें, तो हरेक मरीज़ की सेवा 14 राजनीतिक कार्यकर्ता कर सकते हैं, पर क्या आपको तस्वीर ऐसी ही दिख रही है? क्या राजनेता व कार्यकर्ता अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, लेकिन पटना और बिहार में जब पप्पू यादव पीड़ितों के लिए काम करते दिखते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे मरीज़ों को बिस्तर दिलाने की कोशिश में लगे हैं, तो उनसे क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। गुरुद्वारों के लोग लगे हैं, मस्जिदों, मंदिरों और चर्च में भी कुछ हद तक लगे हैं, लेकिन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को सार्वजनिक करने वाले अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से सरकारें नहीं चूक रही।

ये राजनीतिक कार्यकर्ता भले ही वेंटिलेटर, बेड नहीं दे सकते, ऑक्सीजन पैदा नहीं कर सकते, वैक्सीन की खुराब नहीं बना सकते, लेकिन उनके ज़मीन पर उतरने से इतना तो तय है कि दवाओं और ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाज़ारी रुक जाती। विधायकों और सांसदों के सक्रिय होने पर अस्पताल बिस्तर होने के झूठे आंकड़े नहीं दिखा पाते। लाखों के फ़र्ज़ी बिल बनाने की हिम्मत नहीं कर पाते। राजनीतिक दल कोरोना पीड़ित परिवारों के लिए कम से कम दो वक्त का भोजन उपलब्ध तो करा ही सकते थे और इतनी उम्मीद तो उनसे की ही जा सकती है कि वे मरने वालों के शवों का सम्मानजनक अंतिम संस्कार ही करवा दें।

वर्ष 2019 के आम चुनाव में भाजपा के 436 उम्मीदवारों में से 303 सांसद चुने गए, तो कांग्रेस के 421 उम्मीदवारों में से 52 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे, इसी अनुपात में दूसरे दलों के भी उम्मीदवार हैं। सांसदों और विधायकों की बात छोड़िए, यदि ये हारे हुए लोग ही इस संकट काल में सेवा के लिए मैदान में उतर जाएं, तो हो सकता है कि अगली बार उनकी किस्मत बदल जाए।

यहां जयपुर से कई कई बार भाजपा सांसद और विधायक रहे गिरधारी लाल भार्गव का ज़िक्र ज़रूरी लगता है। जब भार्गव विधायक बने, तो उन्होंने जयपुर के श्मशानों में गंगा में प्रवाहित होने के इंतज़ार में बरसों से पड़ी हज़ारों अस्थियों को प्रवाहित करने का संकल्प लिया और वह हर शनिवार की रात रोडवेज की बस में बैठकर एक बोरा अस्थियां हरिद्वार लाते। अगले दिन संस्कार और सम्मान के साथ उन्हें प्रवाहित कर देते। नतीजा जब एक बार कांग्रेस ने उनके ख़िलाफ़ जयपुर के पूर्व महाराजा भवानी सिंह को उतार दिया, तब एक नारा चला 'जिसका कोई न पूछे हाल, उसके संग गिरधारी लाल।' उस चुनाव का नतीजा यहां लिखने ज़रूरत नहीं है और यह राजनेता के लिए सबक़ भी हो सकता है, गर वह सीखना चाहे।

रोज़गार .................................................................................................

# फाइनेंशियल एडवाइजर बनकर संवारें कैरिअर

वित्तीय मामलों में ज़्यादातर आंकड़ों का खेल होता है। इसलिए एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर बनने के लिए ज़रूरी है कि आपको फाइनेंस की भाषा की अच्छी समझ हो। एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर वह होता है जो अपने ग्राहकों को अच्छी सर्विस, वित्तीय राय और सही गाइड कर सके। ये कई तरह की सर्विस देते हैं, जिनमें शामिल है। 'इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इनकम टैक्स प्रीप्रेशन और इस्टेट प्लानिंग। फाइनेंशियल एडवाइजर को फाइनेंशियल प्लानर भी कहा जाता है। फाइनेंस के सेक्टर में हो रहे विकास के कारण आज इस क्षेत्र में कैरिअर की काफी बेहतर संभावनाएं बनी हैं।

### फाइनेंशियल एडवाइजर का काम

अपने ग्राहकों की वित्तीय स्थिति कोा सुधारने के लिए उपयोगी सलाह देने का काम फाइनेंशियल एडवाइजर करते हैं। इनका काम अपने ग्राहकों को निवेश, बीम, बचत योजनाओं, कर्ज़ आदि के बारे में सही सलाह देना होता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होता है कि ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा और कम से कम नुकसान हो।

### योग्यता

फाइनेंस सेक्टर में कैरिअर बनाने के लिए आप कैट एग्जाम के ज़रिये भारत के किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इस सेक्टर में उच्च शिक्षा के लिए किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री का होना ज़रूरी है। वैसे, पहले केवल कॉमर्स के छात्र ही इस क्षेत्र में भविष्य बनाते थे, लेकिन इसके बढ़ते क्षेत्र को देखते हुए बीएससी (मैथ बायो), बीए, बीबीए और बीई के छात्र भी एडमिशन ले सकते हैं। इस क्षेत्र में कैरिअर बनाने के लिए आप चाहें तो एमबीए इन फाइनेंस, एमएस इन फाइनेंस, मास्ट डिग्री इन फाइनेंशियल इंजीनियरिंग , पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, एडवांस डिप्लोमा इन बैंकिंग एण्ड फाइनेंस, मास्टर्स इन कमोडिटी एक्सचेंज आदि कोर्स कर सकते हैं।

### नौकरी के अवसर

विशेषज्ञों के मुताबिक फाइनेंशियल एडवाइजर किसी कंपनी में अकाउंटेंट, ऑडिटर इकोनामिस्ट, इंश्योरेंस सेल्स एजेंट, इंश्योरेंस अंडरराइटर, लोन ऑफिसर पर्सेनल फाइनेंशियल एडवाइजर, टैक्स इंस्पेक्टर, रेवेन्यू एजेंट आदि के तौर पर काम कर सकते हैं। फाइनेंस में ग्रेजुएशन करने के बाद आप किसी बिजनेस अख़बार पत्रिका आदि में संवाददाता और वित्तीय विश्लेषक के रूप में काम कर सकते हैं। बैंक, इंश्योरेंस और ट्रेडिंग कंपनियां अपने वित्तीय उत्पादों मसलन, कर्ज़, इंश्योरेंस शेयर, ब्रांड्स और म्युचुअल फंड बेचने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर्स को नियुक्त करती है। विदेशों में भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स की मांग काफी ज़्यादा है। प्रोफेशनल्स चाहें तो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कंपनी लैंडिंग एंड बारोइंग, मल्टी करेंसी ट्रेडिंग आदि फाइनेंशियल कंपनियों में नौकरी की तलाश कर सकते हैं।

### सैलरी वॉच

फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर कैरिअर की शुरुआत करने पर ज़्यादातर कंपनियां सैली के साथ साथ कमीशन भी देती हैं। वैसे, शुरुआती दौर में सैलरी 20 हजार से 30 हजार रुपयेप्रति माह हो सकती हैं। अनुभवी प्रोफेशनल्स की सैलरी 1 लाख से 02 लाख रुपये प्रति माह तक हो सकती है।

### प्रमुख संस्थान

डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। टीकेडब्ल्यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस नई दिल्ली।

द इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया, हैदराबाद। इंस्टीटयूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसर्च चेन्नई। जेवियर इंस्टीटयूट ऑफ मैनेजमेंट, भुवनेश्वर।

## मछली ने बदली मछुआरे की किस्मत, 72 लाख में बिकी

पाक : बलूचिस्तान कब किस पर और किस पर और किस तरह से मेहरबान हो जाए कोई नहीं जानता। इसका उदाहरण देखने को मिला पाकिस्तान में, जहां मछली ने एक मछुआरे की किस्मत बदल दी। बलूचिस्तान ग्वादर में रहने वाले एक मछुआरे के हाथ करीब 48 किलोग्राम की एक दुर्लभ क्रोकर मछली लग गई। नीलामी के दौरान इसकी कीमत 72 लाख पाकिस्तानी रूपये में बिकी। मछुआरा साजिद हाजी अबू बकर एक मछली बेचकर ही लखपति बन गया।

## लीबिया में मिले तीन प्रवासी बच्चों के शव

**काहिरा :** संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी ने कहा कि संभवतया यूरोप जा रहे प्रवासियों के भूमध्य सागर में डूबने से मारे गए लोगों में तीन बच्चे भी शामिल हैं, जिनके शव बहकर लीबिया के तटीय शहर जुवारा में पाए गए हैं। जुवारा शहर राजधानी त्रिपोली के सौ किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इनमें छह माह के बच्चे और तीन वर्ष के बच्चे के शव शामिल हैं। बेहतर ज़िन्दगी की तलाश में खतरनाक रास्तों से निकले बच्चे बेवजह ज़िन्दगी से हाथ धो रहे हैं।

## बच्चों के शव मिलना पहली घटना नहीं : टूडो

टोरंटो : प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो ने कहा कि एक स्कूल परिसर में 200 से अधिक बच्चों के शव दफ़न पाए जाने की घटना। इस तरह की इकलौती घटना नहीं है। इस स्कूल को कभी कनाडा का सबसे बड़ा आवासीय विद्यालय माना जाता था। इस घटना के सामने आने के बाद सामुदायिक नेताओं ने मांग की कि हर उस स्थान की जांच की जाए जहां कभी कोई आवासीय स्कूल रहा हो। इसी की पृष्ठभूमि में टूडो ने यह टिप्पणी की।

## पाक में कई जगह 60 साल का सबसे बड़ा जल संकट

पेशावर/कराची : अर्थ संकट से जूझ रहा पाकिस्तान इन दिनों तापमान बढ़ने के साथ साथ 60 वर्ष के सबसे बड़े जल संकट का सामना कर रहा है। जल व स्वच्छता एजेंसी ने रावलपिंडी में बहुत कम जलापूर्ति की बात स्वीकारी वही सिंधु नदी प्रणाली प्राधिकरण (आईआरएसए) को पंजाब और सिंध प्रांतों में फिलहाल धान की बुवाई न करने की सलाह तक देनी पड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी शहर में 59 मिलियन गैलन की ज़रूरत के मुकाबले रोज़ाना महज 46 एमजीडी जलापूर्ति ही हो रही हे। इस बीच, पेशावर क्षेत्र में जल स्तर भी घटकर 650 फीट रह गया है। जबकि रावल और खानपुर बांधों से आपूर्ति में कटौती ने पानी की कमी को और बढा दिया है।

# नए शिक्षा मॉडल के दूरगामी प्रभाव

**दर्शनी प्रिय**

आधुनिक शिक्षा परिवर्तनगामी समय की मांग है। समस्त विश्व समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित कर रहा है। भारत को भी इस मोर्चे पर अग्रसर होने की तत्काल आवश्यकता है। शिक्षा नीति के बदले कलेवर को इसी समग्रता में देखा जाना चाहिए। शिक्षा के आधुनिक मॉडल से देश के नौनिहालों का सर्वांगीण विकास और ढहती शिक्षा व्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सकता है। भारतीय शिक्षा पद्धति आज भी कई मायनों में असमीचीन प्रतीत होती है। तकनीकी सुगमता से दूर पारंपरिक पठन-पाठन छात्रों की प्रगति को लगातार बाधित कर रही है। इस दिशा में संभावनाओं की तलाश 1986 के बाद के सालों में शिक्षा नीति के रूप में आंशिक ही सही, लेकिन फलीभूत हो पाई, हालांकि परिणाम औसत रहे। मौजूदा समय में शिक्षा की आधुनिक अवधारणा पुन: रेखांकित हुई है। वैश्विक महामारी के चलते उपजे संकट ने ई-पाठयक्रम और डिजिटल शिक्षा के महत्व को बढ़ाया है।

एक आंकड़े के अनुसार देश में लगभग डेढ लाख सरकारी और निजी स्कूल हैं, जिनमें तकरीबन सात लाख कक्षाएं हैं। वहीं कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर दो लाख कक्षाएं हैं। इस प्रकार देश में कुल नौ लाख कक्षाएं हैं लेकिन ज़्यादातर कक्षाओं में ब्लैकबोर्ड, फर्नीचर, पंखे और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का घोर आभाव है। देश में करीब साठ वर्ष पहले चलाए गए ब्लैकबोर्ड अभियान अब तक लक्ष्य नहीं हासिल कर सका है। यह न केवल चिंतनीय, बल्कि सरकारी व्यवस्था पर प्रश्न भी खड़े करती है। ऐसे में समग्र डिटिजलीकरण कार्यक्रम की कामयाबी पर शक पैदा होता है।

दूर-दराज़ के स्कूलो को इंटरनेट से तभी जोड़ा जा सकेगा, जब वहां बिजली मुकम्मल रूप से पहुंच सके। तभी स्मार्ट क्लास की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि देश के अनेक राज्यों के सरकारी स्कूलों में अभी बिजली नहीं पहुंची है। मार्च, 2017 तक देश के सैंतीस प्रतिशत से अधिक सरकारी स्कूल बिजली कनेक्शन से दूर थे। देश के अधिकतर स्कूलों में स्वच्छ पानी, शौचालय और सतत् बिजली आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। कई स्कूल तो ऐसे हैं, जहां बच्चों के बैठने के लिए टाट, पढ़ने के लिए ब्लैकबोर्ड और अध्यापकों के लिए कुर्सी मेज तक नहीं है। ऐसे में बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देने की संभावना और स्कूलों को स्मार्ट क्लास की राह पर आगे बढ़ाने की बात बेमानी लगती है।

गैर-सरकारी संस्था चाइल्ड रिलीफ एंड यू (क्राई) के एक सर्वे 'लर्निंग ब्लॉक्स' के मुताबिक भारत के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल किसी शिक्षण संस्थान की बुनियाद आवश्यकता भी पूरी नहीं कर पाते। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों की तैयारी सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों में ई-शिक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल कटेंट और क्षमता निर्माण हेतु एक समर्पित इकाई की ज़रूरत है।

विडंबना है कि भव्य परिसर, बेहतर संसाधन और स्कूलों की संख्या

**दूर-दराज़ के स्कूलो को इंटरनेट से तभी जोड़ा जा सकेगा, जब वहां बिजली मुकम्मल रूप से पहुंच सके। तभी स्मार्ट क्लास की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि देश के अनेक राज्यों के सरकारी स्कूलों में अभी बिजली नहीं पहुंची है। मार्च, 2017 तक देश के सैंतीस प्रतिशत से अधिक सरकारी स्कूल बिजली कनेक्शन से दूर थे। देश के अधिकतर स्कूलों में स्वच्छ पानी, शौचालय और सतत् बिजली आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। कई स्कूल तो ऐसे हैं, जहां बच्चों के बैठने के लिए टाट, पढ़ने के लिए ब्लैकबोर्ड और अध्यापकों के लिए कुर्सी मेज तक नहीं है। ऐसे में बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देने की संभावना और स्कूलों को स्मार्ट क्लास की राह पर आगे बढ़ाने की बात बेमानी लगती है।**

बढ़ाने के नाम पर हर वर्ष एक बड़ी धनराशि आबंटित की जाती है, पर परिणाम अब तक शून्य है। दूसरी ओर विभिन्न राज्यों में बड़ी तादाद में सरकारी स्कूलों को बंद होना भी चिंता की बात है। सुदूर इलाकों के कई ऐसे स्कूल हैं, जो वित्त पोषण और संसाधनहीनता के चलते बंद होने के कगार पर हैं। दुर्गम इलाकों में बसे इन स्कूलों की सुध लेने वाला कोई नहीं। वहां शिक्षकों की लगातार घटती अनुपस्थिति चिंता पैदा करती है। दिसंबर 2008 में देश के सभी छह से चौदह वर्ष की आयुवर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया था, लेकिन सरकारी आंकड़ों के हवाले से यह बात छिपी नहीं है कि ऐसे बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो प्राथमिक शिक्षा से वंचित है। बड़ी तादाद में बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं।

ज़ाहिर है, सिर्फ बड़े-बड़े मसौदों से बात नहीं बनने वाली। स्कूलों में बुनियादी स्तर पर द्रुत गति से कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुधारना और उन्हें ज़रूरी सुविधाएं भी मुहैया करानी होगी। दुर्गम इलाकों के स्कूलों में बिजली पहुंचाने को प्राथमिकता देनी होगी, ताकि समग्र डिजिटलीकरण की रफ्तार तेज़ हो सके। विजुअल क्लास की मदद से बच्चों को रोचक ढंग से पढ़ाने की व्यवस्था की जाए, ताकि उनमें पढ़ाई के प्रति रुचि जगाई जा सके। पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करने के लिए शिक्षण संस्थानों में शाम की कक्षा पर विचार किया जा सकता है। व्यावसायिक शिक्षा को सभी शैक्षिक संस्थानों के साथ एकीकृत किया जाए, तो इच्छित परिणाम हासिल किए जा सकेंगे।

एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था नए भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है। अन्य देशों की तुलना में भारत में शिक्षणा संस्थान शुरू करने की सबसे कठिन शर्ते हैं हालांकि यह काफी हद तक संसाधन और निवेश जुटाने, भूमि मानदंड और अन्य शर्तो से संबंधित है। समुचित शिक्षा व्यवस्था के लिए एक अनुरूप विनियामक व्यवस्था होनी चाहिए, जो स्कूलों के अलगाव और एकाकीपन को ख़त्म करेगा।

इन तमाम चुनौतियों से निपटने के अलावा शैक्षणिक संस्थानों में रिक्त पड़े पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरना होगा और विश्वस्तरीय संस्थागत सुविधाएं मुहैया कराने के प्रयास भी सुनिश्चित करने होंगे, ताकि छात्रों को अध्ययन और विकास का उचित माहौल मिल सके। समुचित वातावरण, उन्नत संसाधनों तथा योग्य प्राध्यापकों की उपस्थिति में ही छात्रों का चहुमुंखी विकास संभव है। भारत को अगर शिक्षा के क्षेत्र में अपना दबदबा क़ायम करना है, तो शिक्षण संस्थानों के प्रति छात्रों के आकर्षण को बनाए रखना होगा, साथ ही शिक्षा के लब्धप्रतिष्ठित और मानक संस्थानों को पुनर्जीवित कर उन्हें नया रंग देना होगा।

देश का प्रत्येक छात्र समेकित शिक्षा से जुड़ सके, इसके लिए महती प्रयास ज़रूरी होंगे। इसके तहत पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान पद्धति को शामिल करना, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन और निजी स्कूलों की मनमानी से रोकने पर समग्रता से कार्य करना होगा। साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण में व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को सभी स्कूलों से जोड़ने की कोशिश करनी होगी। पुरानी शिक्षा प्रणाली में बदलाव करते हुए उच्च गुणवत्ता और व्यापक शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना ज़रूरी है। परंपराओं, संस्कृतियों और भाषाओं की विविधता को ध्यान में रखते हुए तेज़ी से बदलते समाज की ज़रूरतों के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए।

शिक्षा की बदहाली का आलम यह है कि स्कूली पढ़ाई करने वाले नौ छात्रों में से सिर्फ एक कॉलेज तक पहुंच पाता है। भारतीय छात्र विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए हर वर्ष सात अरब डॉलर यानि करीब तैंतालीस हज़ार करोड़ रुपए ख़र्च करते हैं। हमारे यहां मौलिक शोध पर बहुत कम ख़र्च होता है और तमाम शैक्षिक संस्थान भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं। आंकड़े बताते है कि इतनी भारी भरकम रकम खर्च के

बाक़ी पेज 11 पर

## वैक्सिनेशन में युवाओं को मिले तरजीह : उच्च न्यायालय

दिल्ली हाईकोर्ट ने वैक्सिनेशन पर केन्द्र सरकार की खिंचाई की है। अदालत ने कहा कि युवा पीढ़ी को पहले टीका लगाया जाना चाहिए था क्योंकि वह देश का भविष्य है, लेकिन बुजुर्गों को प्राथमिकता दी गई। कोर्ट ने साफ किया कि हम ये नहीं कह रहे कि बुजुर्गों का जीवन अहम नहीं है। बुजुर्ग व्यक्ति परिवार को बड़ा भावनात्मक समर्थन देते हैं। जस्टिस विपिन सांघी ने कहा कि दूसरी लहर में युवा ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्हें ही टीके नहीं मिल रहे थे। हमें यह पॉलिसी समझ में नहीं आई। अपने 18 से 44 वर्ष के लिए टीके घोषणा की लेकिन आपके पास टीका है ही नहीं। फिर घोषणा क्यों की? हमें युवाओं के टीकाकरण की ज़्यादा ज़रूरत है। सभी को बचाना चाहिए लेकिन चुनना हो तो हमें युवाओं को पहले बचाना होगा क्योंकि 80 वर्ष का व्यक्ति ने अपनी ज़िन्दगी जी ली।

अखिलेश आर्येंदु

# ज़हरीला होता भूजल एक अहम मुद्दा

भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में पीने लायक़ साफ पानी मिलना किसी चुनौती से कम नहीं है। भारत में मात्र 30 प्रतिशत लोगों को पीने लायक़ पानी उपलब्ध है। उत्तर और दक्षिण भारत के अनेक इलाकों में भूजल में कई तरह के रासायनिकों के मिश्रण की वजह से शुद्ध पानी की उपलब्धता कठिन होती जा रही है। इस दिशा में सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेकर जल मंत्रालय और राज्य सरकारों को ठोस क़दम उठाने का निर्देश दिया था, लेकिन समस्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। गुजरात के कच्छ, राजस्थान के कई ज़िले, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भूजल मिश्रण की समस्या विकराल होती जा रही है। राजस्थान के कई ज़िलों में लोगों को कई किमी पैदल चलकर पीने का पानी मिलता है, वह भी रासायनिक तत्वों से युक्त।

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि सेहत के लिए ख़तरनाक रासायनिक तत्वों की मिलावट वाले दूषित पानी की उपलब्धता से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और असम हैं। पर्यावरण मंत्रालय की मदद से केन्द्रीय एजेंसी 'एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली' (आईएमआईएस) द्वारा देश में पानी की गुणवत्ता की सर्वाधिक 19,657 बस्तियों और इनमें रहने वाले 77.70 लाख लोग ज़हरीला पानी पीने की वजह से प्रभावित है। आईएम आईएस द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को सौंपे गए आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में 70,736 बस्तियां फ्लोराइड, आर्सेनिक, लौहतत्व और नाइट्रेट सहित दूसरे लवण एवं भारी धातुओं के मिश्रण वाले दूषित जल से प्रभावित है। इस पानी से सीधे सीधे 47.41 करोड़ आबादी प्रभावित है।

राजस्थान में फ्लोराइड, नाइट्रेट और लवणयुक्त भूजल का प्रकोप सबसे ज़्यादा है। राज्य में 5996 बस्तियों के 40.49 लाख लोग फ्लोराइड 12,606 बस्तियों में रहने वाले 28.53 लाख लोग लवणयुक्त और 1050 बस्तियों के 8.18 लोग नाइट्रेट मिश्रित पानी के इस्तेमाल को विवश हैं। वहीं असम के भूजल का बहुत बड़ा हिस्सा आर्सेनिक के मिश्रण की वजह से इस्तेमाल के क़ाबिल नहीं रह गया है। एक आंकड़े के मुताबिक असम की 4514 बस्तियों में रहने वाली सत्रह लाख की आबादी को आर्सेनिक युक्त पानी पीना पड़ रहा है। इससे कैंसर, हृदय संबंधी बीमारियां और पेट की बीमारियों से लोगों को दोचार होना पड़ रहा है।

कंसर्वोच्च न्यायालय ने भूजल के प्रदूषित होने के मद्देनज़र बड़ी औद्योगिक इकाइयों को बंद करने या आबादी से दूर स्थापित करने का आदेश दिया था। उसका पालन कुछ राज्य सरकारों ने किया, लेकिन आज भी दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, हरिद्वार, फरीदाबाद, गुरुग्राम और दूसरे तमाम शहरों में औद्योगिक गतिविधियां जारी हैं जिस पर तत्काल ग़ौर करने की ज़रूरत है।पश्चिम बंगाल, राजस्थान और असम की तरह ऐसा तीसरा राज्य है, जहां पानी में आर्सेनिक, नाइट्रेट जैसे ज़हरीले रासयनिक तत्व बहुतायत में पाए जाते हैं।

असम सरकार ने इस दिशा में कुछ कोशिशें की हैं, लेकिन भूजल के प्रदूषित होते जाने में कोई ऐसा क़दम अभी नहीं उठाया गया है, जिससे राज्य के सभी लोगों को साफ और शुद्ध पीने लायक़ पानी मिल जाए।

इसी तरह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, मेरठ, जौनपुर, बस्ती सहित अनेक ज़िलों में आर्सेनिक और दूसरे रासायनिक तत्वों का मिश्रण भूजल में पाया गया है। चंडीगढ़ स्थित लेबोरेटरी के परीक्षण के मुताबिक दिल्ली में ज़मीन के नीचे पानी में क्लोराइड की मात्रा तय सीमा से एक हजार प्रतिशत तक अधिक पाई गई। इसी तरह कैल्शियम, मैग्नीशियम, जस्ता, सल्फेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड, फेरिक (लोहा) और कैडमियम की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। इन तत्वों से युक्त पानी पीने से हृदयघात, किडनी पर बुरा असर, लीवर का संक्रमण, गैस्ट्रिक कैंसर, दांत, संबंधित बीमारियां, नर्वस सस्टम पर बुरा असर, त्वचा संबंधी रोग, तनाव, अस्थमा, थॉयराएड, हृदय संबंधी रोग, डायरिया और आंख संबंधी अनेक समस्याएं देखी जा रही हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने भूजल के प्रदूषित होने के मद्देनज़र बड़ी औद्योगिक इकाइयों को बंद करने या आबादी से दूर स्थापित करने का आदेश दिया था। उसका पालन कुछ राज्य सरकारों ने किया, लेकिन आज भी दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, हरिद्वार, फरीदाबाद, गुरुग्राम और दूसरे तमाम शहरों में औद्योगिक गतिविधियां जारी हैं जिस पर तत्काल ग़ौर करने की ज़रूरत है।

पश्चिम बंगाल, राजस्थान और असम की तरह ऐसा तीसरा राज्य है, जहां पानी में आर्सेनिक, नाइट्रेट जैसे ज़हरीले रासयनिक तत्व बहुतायत में पाए जाते हैं। कोलकाता, उत्तर परगना, दक्षिण, परगना, मुर्शिदाबाद जैसे अनेक जनपदों के भूजल में आर्सेनिक का होना सामान्य बात है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य की 17,650 बस्तियों के 1.10 करोड़ लोग ज़हरीले पानी की उपलब्धता वाले इलाके में रहते हैं। इन इलाकों में रहने वाले ज़्यादातर लोग कैंसर, फेफड़े, आंख की समस्या, अस्थमा, त्वचा संबंधी बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। चिंता की बात यह है कि राज्य सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस क़दम नहीं उठाए हैं, जिससे समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। ग़ौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से लोगों को साफ और शुद्ध पीने लायक़ पानी मुहैया कराना बहुत बड़ी चुनौती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आर्सेनिक का अधिकतम सुरक्षित स्तर दस पार्ट्स प्रति अरब (पीपीबी) माना है। ग़ौरतलब है कि दुनिया के पन्द्रह करोड़ लोग नियमित रूप से इससे अधिक आर्सेनिक युक्त पानी पी रहे हैं। भारत के अलावा बांग्लादेश, अमेरिका सहित दुनिया के ऐसे तमाम देश हैं जहां आर्सेनिक, नाइट्रेट, कुछ खास तरह के लवण भूजल में घुले मिलते हैं। ग़ौरतलब है कि विकसित देशों ने नई तकनीक के ज़रिए भूजल के विषाक्त होने की समस्या को काफी कुछ हल कर चुके हैं, लेकिन भारत, बांग्लादेश जैसे विकासशील देशों में अभी इस दिशा में ऐसा कोई ठोस क़दम नहीं उठाया जा सका है, इससे लोगों को ज़हरीला पानी पीने से छुटकारा मिलता।

नई वैज्ञानिक भूजल शोधन तकनीकि से आर्सेनिक, नाइट्रेट और दूसरे ज़हरीले रसायनों का भूजल में मिश्रित होने की प्रक्रिया को समझ कर भूजल के ज़हरीले होने से रोका जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अपरदन से चट्टानों के माध्यम से चट्टानों में मौजूद खनिज मिट्टी में आर्सेनिक छोड़ते रहते हैं। फिर मिट्टी से यह भूजल में चला जाता है। इसके अलावा मानव गतिविधियां, जैसे खनन और भूतापीय, ऊष्मा उत्पादन, आर्सेनिक के पेयजल में मिलने की प्रक्रिया को बढ़ाते है। इसका एक उदाहरण कोयला जलने के बाद उसकी बची हुई राख है, जिसमें आर्सेनिक और दूसरे ज़हरीले पदार्थ होते हैं, हवा या दूसरे माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ग़ौरतलब है कि भूजल में ज़हरीले तत्वों के मिश्रण, जिस प्रक्रिया से जल को दूषित करते हैं उसे रोकना असंभव नहीं तो मुश्किल ज़रूर है लेकिन नई तकनीक के इस्तेमाल से जल का शोधन कर पीने लायक़ पानी लोगों को मुहैया कराया जा सकता है। प्रदूषित पानी पीने से सेहत पर तो असर पड़ता ही है, जिस जानवर को पिलाया जाता है और खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है वे सभी ज़हरीले तत्वों के असर से दूषित हो जाती हैं। इससे ग्रामीण इलाक़ों के लोगों, जानवरों और खेती पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पानी में फ्लोराइड से फ्लूरोसिस, नाइट्रेट से श्वास संबंधी बीमारियां, लौह युक्त पानी से ऑस्ट्रियोपोरोसिस, आर्थराइटिस और आर्सेनिक युक्त दूषित जल से कैंसर जैसी बीमारियों का ख़तरा बढ़ जाता है। यानि अगर भारत के लोगों को शुद्ध पानी मुहैया करा दिया जाए तो करोड़ों लोग अनेक घातक बीमारियों से बच सकते हैं।

केंद्र सरकार 2024 तक प्रत्येक परिवार को साफ और शुद्ध पीने का पानी मुहैया कराने की योजना पर कार्य कर रही है, लेकिन प्रश्न है कि नदियों, झीलों, नहरों और तालाबों

बाक़ी पेज 11 पर

## सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द

कोरोना महामारी के चलते सरकार ने सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुआई में हुई एक बैठक में यह फैसला लिया गया। परीक्षा रद्द होने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी में छात्रों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है और ऐसे माहौल में तनाव नहीं दिया जा सकता है। बैठक के बाद कहा गया कि सीबीएसई 12वीं कक्षा के छात्रों का रिजल्ट घोषित करने के लिए एक पारदर्शी तरीके से सिस्टम बनाएगा। मालूम हो कि 10वीं की परीक्षा पहले ही रद्द की जा चुकी है। 12वीं की परीक्षा के बारे में निर्णय लेने से पहले निशंक ने सभी सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से भी राय मांगी थी अधिकतर राज्यों ने परीक्षा रद्द करने के समर्थन में ही राय दी थी।

## ख़ास ख़बरें

### नेपाल में संविधान पीठ गठित होगी

काठमांडू: नेपाल के उच्चतम न्यायालय ने प्रतिनिधि सभा को भंग किए जाने के ख़िलाफ़ दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की वरिष्ठता के आधार पर संविधान पीठ गठित करने पर सहमति जताई। द हिमालयन टाइम्स समाचार पत्र की ख़बर के अनुसार पांच सदस्यीय संविधान पीठ के अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में कहा कि वह उच्चतम न्यायालय के कामकाज के नियम में संशोधन करेंगे।

### इस्राईल : राष्ट्रपति रिवलिन ने नेतन्याहू की चुनौती ठुकराई

येरुशलम : प्रधानंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी ने नई इस्राईली सरकार का नेतृत्व करने के लिए दक्षिणपंथी पार्टी के प्रस्ताव की वैधता को चुनौती दी लेकिन राष्ट्रपति रेवेन रिवलिन ने इसे ख़ारिज कर दिया। नेतन्याहू को इसे राष्ट्रपति द्वारा दिया बड़ा झटका माना जा रहा है। नेतन्याहू के पूर्व रक्षामंत्री नफ्ताली बेनेट ने घोषणा की है कि वे मध्यमार्गी विपक्षी नेता यैर लैपिड के साथ गठबंधन करेंगे। इस तरह दोनों नेता बारी-बारी से प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे।

### महाराष्ट्र : सिर्फ अहमदनगर में 10 हज़ार बच्चे मिले संक्रमित

पुणे : देश में कोरोना महामारी की तसरी लहर की आशंकाओं के बीच महाराष्ट्र के अहमदनगर में अकेले मई माह में करीब दस हजार नाबालिग संक्रमित पाए गए। हालांकि प्रशासन का दावा है कि इनमें से 95 प्रतिशत में महमारी के कोई लक्षण नहीं थे, लिहाज़ा हालात काबू में रहे। मई में अहमदनगर में संक्रमण के 86,182 मामले सामने आए थे, जिनमें से 9,928 नाबालिग थे। उनमें 6,700 नाबालिगों की आयु 11 से 18 साल, 3,100 की एक से दस साल और कुछ बच्चे तो एक वर्ष से भी छोटे थे, 95 प्रतिशत से ज़्यादा नाबालिगों में संक्रमण के लक्षण नहीं होने से चिंता की कोई बात नही है।

### देश में अधिकतम बेरोज़गारी न्यूनतम जीडीपी : राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश की अर्थव्यवस्था पर प्रश्न उठाया है। उन्होंने लिखा, 'प्रधानमंत्री के लिए शर्म की बात है कि देश में न्यूनतम जीडीपी है और अधिकतम बेरोज़गारी है। उन्होंने कहा, सरकार इलाज के बजाय जनता को औपचारिकताओं में क्यों फंसा रही है!? राहुल ने टवीट किया, ब्लैक फंगस की दवा की कमी के लिए क्या किया जा रहा है? मरीज़ को दवा मिलने की क्या प्रक्रिया है? कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी देश में ब्लैक फंगस की दवा की कमी पर कुछ दिनों पहले पीएम नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा था।

# वुज़ू, नमाज़ और जिस्मानी सेहत

(2)

जबकि घुटनों के जोड़ सीधी हालत में होते हैं। कोहनियां सीधी खिंची हुई होती हैं और कलाई भी सीधी होती है और उनके तमाम पुट्ठे चुस्त हालत में रहते हैं जबकि पेट और कमर के झुकते और सीध होते वक्त काम करते हैं।

सज्दा : सज्दे में कूल्हे, घुटने, टख़ने और कोहनियों पर झुकाव होता है जबकि टांगों व रानों के पीछे के पुट्ठे और कमर व पेट के पुट्ठे खिंचे हुए होते हैं। और कंधे के जोड़ के पुट्ठे उसको बाहर की ओर खिंचते हैं। उसके साथ साथ कलाई के पीछे के अज़लात भी खिंचे हुए हैं।

सज्दे में औरतों के लिए घुटनों को छाती से लगा लेना अहसन है। यह बच्चेदानी के पीछे गिरने का बेहतरीन इलाज है।

सज्दे के और भी बहुत से जिस्मानी फायदे हैं। दिमाग़ को खून की बहुत ज़रूरत होती है, मगर इसका मुहल्ले वुकूअ ऐसा है कि इस तक खून पहुंचना ज़रा मुश्किल होता है। बिलखुसूस उस वक्त जब शिरयाने भी तंग हों। सज्दा दिमाग़ के लिए खून फराहम करने का बहुत मौज़ूं अमल है।

दिमाग़ आम हालत में बेशतर वक्त दिल में पम्प से ऊंचा रहता है। इसलिए दिमाग़ में खून की सरायत थोड़ी मुश्किल होती है, मगर सज्दे में दिमाग़ दिल से नीचे रहता है इसलिए इस हालत में उसको खून बाआसानी और काफी पहुंचता है। जितना लम्बा सज्दा होगा उतना ही ज़्यादा खून दिमाग़ को पहुंचेगा। चुनांचे नबीए करीम सल्ल० ने सज्दे की फज़ीलत बयान फरमाई है जो लोग नमाज़ के आदी होते हैं उनकी अक़्ल, समझ, याद्दाश्त और नफ़्सियाती सेहत बहुत दिनों तक सही रहती हैं किसी उम्र में भी खुदा वन्दे करीम के हुज़ूर में खुलूसे दिल से किए हुए लम्बे सज्दे, रूहानी, दिमाग़ी और नफ़्सियाती सेहत के लिए मुआविन हैं।

तशहहुद : अत्तहियात पढ़ते वक्त जबकि जिस्म बैठने की हालत में होता है। घुटने और कूल्हे पर झुकाव होता है। टखने और पांव के अज़लात पीछे खींचे हुए होते हैं, कमर और गर्दन के पुट्ठे खिंचे हुए होते है।

सलाम : सलाम फेरते समय गर्दन के दाएं और बाएं तरफ के पुट्ठे काम करते हैं।

बाजमाअत नमाज़ : नमाज़ बाजमआत की बिना पर एक नमाज़ी को दिन में पांच मरतबा बाक़ायदगी के साथ मस्जिद की तरफ जाना पड़ता है। इस तरह जिस्म के तमाम आज़ा की वरजिश होती रहती है। मस्जिद की नेक फज़ा में अपने हमउम्र व ग़मगुसार अहबाब से बातचीत व दूसरी मसरूफियात बूढ़े और ज़ईफ़ लोगों की तमानियत का मूजिब बनती है और उनके समय का बेहतरीन मसरूफ है। इसके मुक़ाबले में मग़रिबी सोसायटी में बूढ़े लोगों की क़यामगाहों की कसमपुर्सी किसी जानने वाले से छुपी नहीं है। हक़ीक़त में यह दुनिया में दोज़ख़ का नमूना पेश करती है जबकि हमारे बुजुर्ग बार-बार मस्जिद में जाकर जो ज़ेहनी और रूहानी सकून हासिल करते हैं। दुनिया की कोई इक़ामत गाह उसकी नज़ीर पेश नहीं कर सकती। इस तरह बाजमाअत नमाज़ ने मुस्लिम सोसायटी को बुढ़ापे की इक़ामतगाहों से बेनियाज़ कर दिया है।

> **वुज़ू और जरासीम से बचाव : वुज़ू हिफ़्ज़ाने सेहत के ज़र्री उसूलों में से है। यह जरासीम के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी ढाल है। बहुत सी बीमारियों जरासीम की वजह से पैदा होती है। यह जरासीम हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। हवा, ज़मीन, और हमारे इस्तेमाल की हर चीज़ पर यह मूज़ी मुसल्लत हैं। जिस्मे इंसानी की हैसिअत एक क़िले की सी है। कोई दुश्मन उसमें दाख़िल नहीं हो सकता, सिवाए सूराखों या जख़्मों के रास्तों में मुंह और नाक के सूराख़ हर वक्त जरासीम की ज़द में है।**

तहारत व पाकीज़गी : ''सफाई ईमान की एक शाख़ है, इस्लाम की बुनियाद पाकीज़गी पर है।''

इस हदीस से सफाई और पाकीज़गी की अहमियत इस क़दर वाज़ेह है कि उसे मज़ीद बयान करने की ज़रूरत नहीं। अब हम उन बीमारियों का ज़िक्र करेंगे जो इस्लाम के बुनियादी उसूलों से इन्हिराफ से पैदा होती है।

1. 'पिलोनिडल साइनस' यह एक बालदार फोड़ा है जो पाखाने की जगह के क़रीब हो जाता है, इसका इलाज ऑपरेशन के बग़ैर नहीं हो सकता।

2. 'पाइलोनेफरटिस' पेशाब के रास्तों और गुर्दों में पीप का पैदा हो जाना। बिलख़ुसुस औरतों में पाखाने के जरासीम (मसलन ई० गोली) पेशाब की नाली में आसानी से दाख़िल होकर जलन और पीप पैदा कर देते हैं और उससे आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों की मोहलिक बीमारी लाहिक़ हो जाती है जिसका पता बाज़ दफ़ा उस वक्त चलता है जब वह लाइलाज हो जाती है।

वुज़ू और जरासीम से बचाव : वुज़ू हिफ़्ज़ाने सेहत के ज़र्री उसूलों में से है। यह जरासीम के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी ढाल है। बहुत सी बीमारियों जरासीम की वजह से पैदा होती है। यह जरासीम हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। हवा, ज़मीन, और हमारे इस्तेमाल की हर चीज़ पर यह मूज़ी मुसल्लत हैं। जिस्मे इंसानी की हैसिअत एक क़िले की सी है। कोई दुश्मन उसमें दाख़िल नहीं हो सकता, सिवाए सूराखों या जख़्मों के रास्तों में मुंह और नाक के सूराख़ हर वक्त जरासीम की ज़द में है। और हमारे हाथ उनकी जिस्म के अंदर ले जाने में मदद करते हैं। वुज़ू के ज़रिए हम न सिर्फ उन सूराखों को बल्कि अपने जिस्म के हर हिस्से को जो कपड़े से ढंका हुआ नहीं है और आसानी से जरासीम की आमाजगाह बन सकता है, दिन में कई बार धोते हैं लिहाज़ा वुज़ू हमें बहुत सी बीमारियों से महफूज़ रखने का ज़रीआ है।

इस सिलसिले में सरवरे क़ाएनात सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के मुन्दर्जा ज़ैल फरमान की वज़ाहत भी ज़रूरी है।

जो शख़्स अपने लिबास को टखनों के नीचे पहनेगा, जहन्नम में जाएगा।''

उलमा इस हदीस की जो भी वजह बताएं मगर इसके तिब्बी फवाएद जानने ज़रूरी हैं। अगर आपका लिबास टखनों के नीचे तक होगा तो लाज़िमन ज़मीन की गंदगी व अलाइश से, जिसमें बहुत सी बीमारियों के तरासीम होते हैं, आलूदा हो जाएगा और यह जरासीम घर के अंदर पहुंचकर आपको और आपके अहलो अयाल को बीमारी कर सकते हैं, वुज़ू टखनों के ऊपर तक के जिस्म को साफ़ कर सकता है, मगर लिबास से गंदगी नहीं हटा सकता। ❑❑

## नूरे क़ुरआन

### ( सूरा अल फज्र नं० 89 )

### अनुवाद और व्याख्या : शैख़ुल हिन्द र.अ.

प्रारंभ करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो असीम कृपालु महादयालु है।

**क़सम है फज्र की ( प्रातःकाल ) और दस रातों की ओर जुफ्त और टांक की और उस रात की जब रात को चले।**

हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर साहब लिखते हैं, कुर्बानी की ईद की प्रातः बड़ा हज होता है और उससे दस रात पहले और जुफ्त और टांक रमज़ान की आख़िरी दहाई में है और जब रात को चले (अर्थात् रसूल मैराज के लिए) यह तमाम घड़ियां पवित्र थीं इसलिए इनकी क़सम खाई।

चेतावनी : वल्लैली इजा यस्त्र का अर्थ बहुधा तफसीर करने वालो ने रात के गुज़रने या उसके अंधकार के फैलने के लिये है। गोया प्रातःकाल की क़सम के मुक़ाबले में रात के जाने या आने की क़सम खाई है जैसा कि जुफ्त के मुक़ाबले में टांक की क़सम खाई गई दस रातों से भी संभवतः सामान्य दस रातें मुराद हों क्योंकि उनमें भी मुक़ाबला पाया जाता है। महीने के प्रारंभ की दस रातें अव्वल रोशन होती हैं फिर अंधेर और अन्त की दस रातें प्रारंभ में अंधेरी होती है। और फिर रोशन होती हैं और बीच की दस रातों का हाल इन दोनों से अलग है। अर्थात् इस भिन्नता और मुक़ाबले से संकेत कर दिया कि आदमी को ऐशो-आराम मुसीबत व तंगी या बहुलता की जो हालत पेश आये उस पर असंतोष न करें और यूं न समझें कि अब इसके ख़िलाफ़ दूसरी हालत सामने न आयेगी। उसे याद रखना चाहिए कि अल्लाह संसार में एक वस्तु के मुक़ाबले में दूसरी वस्तु पैदा करता है (जैसे दिन के मुक़ाबले में रात और धनी के मुक़ाबले में निर्धनता)। इसी प्रकार तुम्हारे हालात को भी अपनी तात्विकता के अनुरूप अदल-बदल करता रहता है। अतः आगे जो घटनायें और विषय आ रहे हैं उनमें से इसी नियम पर चेतावनी दी है।

**बुद्धिमानों के वास्ते उन वस्तुओं की क़सम पूरी है।**

अर्थात् यह कसमें साधारण नहीं बहुत विश्वसनीय हैं और बुद्धिमान लोग समझ सकते हैं कि कलाम की दृढ़ता के लिए इनमें एक विशेष बड़प्पन व मान पाया जाता है।

**क्या आपको ख़बर नहीं कि आपके पालनहार ने आद क़ौम इरम क़ौम के साथ कैसा किया।**

आद एक व्यक्ति का नाम है जिससे यह क़ौम सम्बन्धित कर दी गयी। उसकी पूर्वजों में से एक व्यक्ति इरम नामी था। उसकी ओर संबंध करने से संभवतः इस ओर संकेत हो कि यहां आद से प्रथम आद मुराद है आद द्वितीय नहीं और कुछ ने कहा कि आद क़ौम में जो शाही ख़ानदान था इसे इरम कहते थे।

**जो बड़े खम्बों वाले थे।**

अर्थात् सुतून खड़े करके बड़ी-बड़ी इमारतें बनाते या यह मतलब है कि अधिकतर पर्यटन में रहते और ऊँचे सुतूनों पर खेमे तानते थे और कुछ का विचार है कि बड़े खम्बों वाले कह कर उनके ऊंचे क़द और डील डौल को सुतूनों की उपमा दी।

**कि जिनके बराबर शहरों में कोई व्यक्ति पैदा नहीं किया गया।**

अर्थात् उस वक़्त दुनिया में उस क़ौम जैसी कोई मज़बूत और शक्तिशाली जाति नहीं थी या उनकी इमारतें (भवन) अपना जवाब नहीं रखती थीं।

**कि जिनके बराबर शहरों में कोई व्यक्ति पैदा नहीं किया गया।**

अर्थात् उस वक़्त दुनिया में उस क़ौम जैसी कोई मज़बूत और शक्तिशाली जाति नहीं थी या उनकी इमारतें (भवन) अपना जवाब नहीं रखती थीं।

**और समूद क़ौम के साथ जो कुरा की घाटी में पत्थरों को तराशा ( कांटा छांटा ) करते थे।**

कुरा की घाटी उनके स्थान का नाम है जहां पहाड़ के पत्थरों को काट कर बहुत सुरक्षित और मज़बूत मकान मानते थे।

## हम्दे बारी तआला

हफ़ीज़ ताइब

तू ख़ालिक़ हर आलम का या हय या क़य्यूम
हर पल तेरा रंग नया या हय या क़य्यूम
तू ज़ाहिर भी बातिन भी या बारी या फत्ताह
सब में बस कर सबसे जुदा या हय या क़य्यूम
तू है नूरे अर्ज़ो समा या क़ादिर या क़ुद्दूस
नूर से अपने राह दिखा या हय या क़य्यूम
नूर तेरा है ताक़ के अंदर जलता एक चिराग़
या एक तारा मोती सा या हय या क़य्यूम
तू मन्नान है तू मन्नान है तू रहमानो रहीम
अहसन तेरे सब अस्मा या हय या क़य्यूम
पैदा करके इंसां को दी क़ुरआन की तालीम
बख़्शे तू ने नुत्क़ो नवा या हय या क़य्यूम
तूने ज़मीन का फर्श बिछाकर उसको किया सरसब्ज़
तू है कफीले नश्वो नुमा या हय या क़य्यूम
वस्फ़ कहां तक लिखे तेरे ताइब हेचमदान
क्या वो और क्या उसकी सना या हय या क़य्यूम

# मोदीराज के 7 साल किसान के 7 सवाल

**योगेन्द्र यादव**

बीती 26 मई को मोदी सरकार सत्ता में 7 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने देशभर के किसानों को काले झंडों के साथ विरोध मनाने का आहवान किया। संयोगवश आज के दिन किसान आंदोलन को दिल्ली की सीमाओं पर मोर्चा लगाए 06 माह भी पूरे हो रहे हैं। लेकिन किसानों का यह विरोध दिवस केवल 03 कानूनों को रद् करने की मांग तक सीमित नहीं है। सात साल के मोदीराज में किसानों के साथ हुए बर्ताव के आधार पर किसान यह मानने को मजबूर हैं कि मोदी सरकार आज तक देश की सबसे किसान विरोधी सरकार है। किसान मोदी सरकार के 07 वर्ष के बारे में 07 प्रश्न पूछते हैं

**पहला :** मोदी जी की किसान की आय छह वर्ष में दोगुना करने की घोषणा का क्या हुआ? यह घोषणा प्रधानमंत्री ने 28 फरवरी 2016 को की थी। अब छठा वर्ष लग गया है। किसान जानना चाहता है कि अब तक उसकी आय में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन हय पूछने पर सरकार को सांप सूंघ जाता है। आय दोगुनी करना तो दूर की बात है सरकार किसान की आय के आंकड़े देने से कतरा रही है। इस मिशन के लिए बनी सरकारी कमेटी ने बताया था कि 6 वर्ष में आय दोगुनी करने के लिए प्रतिवर्ष किसान को वास्तविक आय 10.4 प्रतिशत बढ़नी चाहिए। पिछले सात सालों में कृषि में औसत वृद्धि की दर (जी.वी. ) केवल 3.3 प्रतिशत प्रति वर्ष रही है, जबकि उसके पहले मनमोहन सिंह सरकार के दस सालों में यह औसत 4.6 प्रतिशत प्रति वर्ष थी।

**दूसरा :** सरकार स्वामीनाथन कमीशन के सुझाए फार्मूले के अनुसार लागत के डेढ़ गुना दाम के वादे से मुकर क्यों गई है? प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेन्द्र मोदी ने देशभर में किसानों को यह वादा किया था। लेकिन सत्ता में आते ही फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर सरकार अपने इस वादे से बिल्कुल मुकर गई। बाद में किसानों की आंखों में धूल झोंकने के लिए मोदी सरकार ने लागत की परिभाषा ही बदल दी। स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार सम्पूर्ण (सी2) लागत की बजाय मोदी सरकार ने आंशिक (ए2+एफएल) लागत का डेढ़ गुना एमएसपी तय कर यह प्रचार कर दिया कि किसानों को बड़ी सौग़ात मिल गई है। सच यह है कि पिछले 07 सालों में एम.एस.पी. की वार्षिक बढ़ोत्तरी की दर यू.पी.ए. सरकार से बहुत कम रहा है।

**तीसरा :** सरकारी गाजे-बाजे की मदद से घोषित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फेल क्यों हो गई? इसकी घोषणा करते समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि पुरानी फसल बीमा योजनाओं में केवल 23 प्रतिशत किसानों को बीमा का कवर मिलता था नई योजना से तीन वर्ष में 2018 तक 50 प्रतिशत किसान फसल बीमा का लाभ पाएंगे। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। 05 वर्ष बाद वर्ष 2020 में फसल बीमा का लाभ उठाने वाले किसान घटकर 13 प्रतिशत रह गए हैं, लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या 4.9 करोड़ से घटकर 2.7 करोड़ हो गई है और बीमा वाली फसल का रकबा 5.2 से घटकर 4.3 करोड़ हेक्टेयर रह गया और तो और खुद भाजपा की गुजरात सरकार ने इस योजना से पिंड छुड़ा लिया है।

**चौथा :** पिछले सात वर्ष में किसान पर आई आपदा में केन्द्र सरकार ने अपने हाथ क्यों झाड़ लिए? पिछले सात साल में दो बार देशव्यापी सूखा पड़ा, असम और बिहार में अभूतपूर्व बाढ़ आई, तमिलनाडु में ऐतिहासिक सूखा पड़ा। वर्ष 2016 में नोटबंदी और 2020-21 में कोरोना लॉकडाउन भी किसान के लिए आपदा के समान रहा। लेकिन केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर सूखा राहत की ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, इसे राज्यों का काम बताया। राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं था, केन्द्र ने उन्हें राहत राशि देने में कंजूसी बरती। सुप्रीम कोर्ट ने केद्र सरकार के 'शतुरमुर्गी रुख' को आड़े हाथों लिया, फिर भी सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया।

**पांचवाँ :** खेती की लागत को घटाने का वादा कर सत्ता में आई मोदी सरकार के कार्यकाल में खाद,

बाकी पेज 11 पर

# अगले वर्ष राज्यसभा की 71 सीटों पर होगा चुनाव
## मोदी की दूसरी पारी में भी 'राज्यसभा में बहुमत' दूर की कौड़ी

लोकसभा में लगातार दो बार बहुमत हासिल करने के बावजूद राज्यसभा में बहुमत हासिल करना भाजपा के लिए फिलहाल दूर की कौड़ी है और अगले वर्ष होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे यह तय करेंगे कि भाजपा राज्य सभा में बहुमत हासिल कर पाती है या नहीं। भाजपा इस समय राज्य सभा में 93 सदस्यों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है और 245 सदस्यों के सदन में उसे अपने दम पर बहुमत हासिल करने के लिए 123 सदस्यों की ज़रूरत पड़ेगी। इस लिहाज़ से भाजपा फिलहाल राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े से 30 सीटें दूर हैं। भाजपा के दूसरे कार्यकाल के दौरान अन्य पार्टियों के करीब आधा दर्जन से ज़्यादा राज्य सभा सदस्यों ने भाजपा के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाई है और इनके दम पर ही भाजपा राज्यसभा में मुस्लिम वुमन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज) बिल, 2019 और जम्मू कश्मीर री ऑर्गेनाइजेशन जैसे बिल पारित करवाने में कामयाब रही है। अगले वर्ष अप्रैल में राज्यसभा के 18, जून में 20 और जुलाई में 33 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होगा और 71 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व 2022 में राज्यसभा की तस्वीर में बड़ा बदलाव आएगा। इस कारण अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनाव 2022 में होने वाले राज्यसभा के चुनाव के लिहाज़ से अहम हो गए हैं क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य में राज्यसभा की 11 सीटें ख़ाली होंगी और इनमें से फिलहाल 05 सीटें भाजपा के पास हैं।

यह सीटें उसे समाजवादी पार्टी के दो पूर्व राज्यसभा सदस्यों संजय सेठ और सुरिंदर सिंह नागर के बाग़ी होकर भाजपा में आने से मिली हैं और उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनाव में 2017 का प्रदर्शन दोहराए बिना भाजपा के लिए सारी 05 सीटें जीतना आसान नहीं होगा। पंजाब में अगले वर्ष राज्यसभा की 07 सीटों पर चुनाव होगा और इनमें से एक सीट फिलहाल भाजपा के पास है लेकिन पंजाब में अब सियासी तस्वीर बदल चुकी है और अकाली दल के साथ उसका गठबंधन नहीं है। राज्य में किसानों के विरोध के बीच भाजपा के लिए सियासी लड़ाई इतनी आसान नहीं हे और अगले वर्ष भाजपा की इस सीट को लेकर भी अनिश्चितता वाली स्थिति है और बहुत संभावना है कि यह सीट भाजपा के हाथ से निकल जाएगी।

भाजपा को आंध्र प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में नुकसान होना तय है। आंध्र प्रदेश की जिन 04 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव होगा उनमें से 03 सीटें इस समय भाजपा के पास हैं क्योंकि टी.डी.पी. के चार सांसद 2019 में पाला बदलकर भाजपा के साथ चले गए थे। अब यह तीनों सीटें आंध्र प्रदेश में सत्ताध ारी वाई0एस.आर. कांग्रेस को चली

**भाजपा को आंध्र प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में नुकसान होना तय है। आंध्र प्रदेश की जिन 04 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव होगा उनमें से 03 सीटें इस समय भाजपा के पास हैं क्योंकि टी.डी. पी. के चार सांसद 2019 में पाला बदलकर भाजपा के साथ चले गए थे। अब यह तीनों सीटें आंध प्रदेश में सत्ताधारी वाई.एस.आर. कांग्रेस को चली जाएंगी।**

जाएंगी। इसी प्रकार राजस्थान में अगले वर्ष जुलाई में भाजपा के कब्ज़े वाली 04 राज्यसभा सीटें ख़ाली हो जाएंगी और राजस्थान में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के पास इन सीटों को जीतने का बड़ा मौक़ा होगा और कांग्रेस विध ानसभा की स्थिति के मुताबिक 03 सीटें आसानी से जीत सकती है। हालांकि इसके लिए कांग्रेस को अपना घर सलामत रखने के लिए कड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी क्योंकि राज्य में सचिन पायलट का धड़ा बग़ावती तेवर दिखाने लगा है। छत्तीसगढ़ में अगले वर्ष जून में हो रहे राज्यसभा की एक सीट के चुनाव में भी भाजपा को इस सीट का नुकसान हो सकता है जबकि असम और हिमाचल प्रदेश की अगले वर्ष ख़ाली होने वाली दोनों सीटें भाजपा के ही खाते में आएंगी।

तमिलनाडू में भाजपा की सहयोगी पार्टी ए.आई.डी.एम. के द्वारा हाल ही में विधानसभा चुनाव में किए गए ख़राब प्रदर्शन के कारण भी राज्यसभा में उसकी स्थिति कमज़ोर होगी। फिलहाल ए.आई.ए.डी.एम.के. के पास राज्यसभा में 06 सदस्य हैं और डी.एम.के के राज्यसभा की संख्या 7 है। तमिलनाडू में फिलहाल राज्यसभा की तीन सीटें ख़ाली हैं और इनमें से दो सीटों पर डी.एम.के. और एक सीट पर ए.आई. ए.डी.एम.के. हिस्से आएगी जबकि अगले वर्ष राज्य की चार सीटों पर सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और चार में से तीन सीटों पर डी.एम.के. का कब्ज़ा हो जाएगा। फिलहाल इन चार सीटों में से दोनों पार्टियों के पास दो-दो सीटें हैं। अगले वर्ष के राज्यसभा के चुनाव के बाद डी.एम.के. सांसदों की संख्या राज्यसभा में दहाई के आंकड़े तक पहुंच सकती है।

### कांग्रेस की यथास्थिति क़ायम रहेगी, बड़ा फायदा होने की उम्मीद कम

कांग्रेस के राज्यसभा में 34 सदस्य हैं और उसकी ताक़त में कोई ज़्यादा वृद्धि के आसार नहीं है। हालांकि उसे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कुल 4 सीटों का फायदा हो सकता है लेकिन असम, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की सीटें उसके हाथ से निकल जाएंगी। असम में अगले साल अप्रैल में कांग्रेस की राज्य यूनिट के अध्यक्ष रिपुन बोरा की सीट सहित 02 सीटें ख़ाली होंगी और इनमें से कांग्रेस को सिर्फ़ एक ही सीट मिलने का अनुमान है लेकिन इसके लिए उसे अपने सहयोगी ए. आई.यू.डी.एफ. के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी और यदि ए.आई.यू.डी.एफ. ने कए राज्यसभा सीट पर दावा ठोक दिया तो कांग्रेस के लिए स्थिति मुश्किल हो जाएगी। हालांकि पार्टी को लग रहा है कि वह पंजाब में अगले वर्ष चुनाव जीत जाएगी और उसे राज्य में कुछ सीटों का फायदा हो सकता है। फिलहाल पंजाब में कांग्रेस के राज्यसभा के चार सदस्य हैं, इन्हें क़ायम रखने के लिए कांग्रेस को विधानसभा में बंपर बहुमत हासिल करना होगा।

# भारतीय फुटबॉल टीम ने दोहा में जारी किया अभियान

विश्व कप 2022 और एशियाई कप 2023 के संयुक्त क्वालीफिकेशन मैचों के लिए क़तर पहुंची भारतीय फुटबॉल टीम के सभी खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों ने कोविड-19 जांच में नेगेटिव आने के बाद अभ्यास शुरू कर दिया है। कप्तान सुनील छेत्री की अगुआई में दोहा पहुंचने के बाद अभ्यास शिविर में भाग लेने से पहले आरटी-पीसीआर जांच के नतीजे आने तक अनिवार्य एकांतवास पर थी।

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के महासचिव कुशल दास ने बताया 'हां, सभी 28 खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ वहां पहुंचने के बाद की गई जांच में नेगेअिव आए हैं। छेत्री की वापसी से उत्साहित भारतीय टीम मेज़बान क़तर के ख़िलाफ़ तीन जून को अपने अभियान की शुरूआत कर चुकी है।

टीम ने पहले यहां एक बायो-बबल (जैव सुरक्षित) के अंदर अभ्यास शिविर में भाग लिया। भारत को दो अन्य मैच बांग्लादेश (सात जून) और अफ़ग़ानिस्तान (15 जून) के ख़िलाफ़ खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है।

क़तर फुटबॉल संघ से अच्छे सहयोग के कारण भारतीय टीम को 10 दिनों के कड़े एकांतवास पर नहीं रहना पड़ा और टीम ने कोविड-19 जांच की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद अभ्यास शुरू कर दिया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने मुख्य कोच इगोर स्टिमक की देख-रेख में खिलाड़ियों के अभ्यास की तस्वीर को सांझा करते हुए टवीट किया, 'आगे की चुनौतियों के लिए तैयारी कर रहे।

कोविड-19 महामारी के कारण इन मैचों को दोहा में खेला जाएगा और उसे घरेलू और दूसरी टीम के मैदान पर मैचों के मूल प्रारूप में नहीं खेला जा रहा है। भारतीय टीम ग्रुप-ई में तीन अंकों के साथ चौथे स्थान पर है। टीम विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने की दौड़ से बाहर हो गई है लेकिन 2023 एशियाई कप में जगह बनाने की संभावना अभी बची हुई है। भारतीय टीम को दो मई से कोलकाता में अभ्यास शिविर में भाग लेना था लेकिन देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण उसे रद्द कर दिया गया था। टीम को दुबई में मैत्री मुक़ाबले खेलने थे लेकिन बाद में वे भी रद्द कर दिए गए।

## शीर्ष खिलाड़ियों से हॉकी के गुर सीख रहे हैं जसकरण

भारतीय हॉकी टीम के मिडफिल्डर जसकरण सिंह ने कहा कि वह कप्तान मनप्रीत सिंह जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों से इस खेल के गुर सीख रहे हैं और उन्हें तोक्यो ओलंपिक टीम में जगह बनाने की उम्मीद है।

हॉकी ओलंपियन और पूर्व भारतीय कोच राजिंदर सिंह जूनियर के पुत्र जसकरण अभी आगामी तोक्यो ओलंपिक के लिए यहां भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) केन्द्र में पुरुष सीनियर कोर ग्रुप के साथ अभ्यास कर रहे हैं।

मनप्रीत, स्ट्राइक मनदीप सिंह और जसकरण सभी पंजाब के जालंधर शहर के रहने वाले हैं। जसकरण ने कहा, 'हमारे घर दो तीन किमी के दायेर में है। ये दोनों मेरी काफी मदद करते हैं। मिडफील्डर और स्ट्राइकर के बीच अच्छी समझ होना महत्वपूर्ण होता है और मुझे लगता है कि हमारे बीच समझ नैसर्गिक तौर पर पैदा हो सकती है क्योंकि हम लंबे समय से एक साथ खेल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2019 में पदार्पण करने वाले इस मिडफील्डर ने कहा, 'यहां तक कि मनप्रीत सिंह और टीम के अन्य वरिष्ठ खिलाड़ी मेरा मार्ग दर्शन करते रहे हैं। जब भी मुझे कोई संदेह होता है तो मैं उनसे बात करता हूं।' जसकरण हाल में अपने तीसरे अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर अर्जेंटीना गए थे। उन्होंने उस दौरे के बारे में कहा 'मैं बहुत लम्बे समय के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहा था इसलिए मैं अपना शत प्रतिशत देने पर ध्यान दे रहा था, मुझे पूरे दौरे में प्रशिक्षकों का पूरा सहयोग मिला। उन्होंने कहा 'वरिष्ठ खिलाड़ियों ने भी मेरा मनोबल बढ़ाया और ओलंपिक चैम्पियन के ख़िलाफ़ खेलने के लिये मुझे आत्मविश्वास दिया। उन्होंने पूरे दौरे में मेरी गलतियों में सुधार करने में मदद की। इसलिए निजी तौर पर मुझे इस दौरे में काफी कुछ सीखने को मिला। ओलंपिक की तैयारियों के बारे में जसकरण ने कहा, 'हम वास्तव में बहुत अच्छी स्थिति में है और ओलंपिक के लिए अच्छी तैयारी कर रहे हैं।'

## आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में इन दो अहम मुद्दों पर होगी चर्चा

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) बोर्ड की वर्चुअल मीटिंग में भारत की टी-20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी पर फैसला टलना तय है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) इस पर अंतिम फैसला करने के लिए यह फैसला किया गया था कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे, लेकिन अब पता चला है कि वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आयोजन को लेकर अमीरात क्रिकेट बोर्ड से चर्चा करने के लिए यूएई में प्रस्तावित है। मीटिंग में किसी ठोस नतीजे की उम्मीद कम है और 1 जुलाई के बाद बीसीसीआई एक और स्पैशल जनरल मीटिंग (एसजीएम) बुलाएगा। आईसीसी 18 जुलाई को शुरू होने वाले वार्षिक सम्मेलन के दौरान अने अन्तिम फैसले की औपचारिक घोषणा कर सकता है।



# आहार में शामिल करें ये पाँच चीजें कोरोना और ब्लैक फंगस दोनों से रहेंगे सुरक्षित

कोरोना और कई प्रकार के फंगस संक्रमण के बढ़ते मामलों ने लोगों को मज़बूत इम्यूनिटी का महत्व समझा दिया है। कोरोना हो या ब्लैक फंगस संक्रमण, विशेषज्ञ कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए दोनों को ही विशेष गंभीर मानते हैं। महामारी की इन विपरीत परिस्थितियों में सभी लोग अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मज़बूत करने के लिए विभिन्न उपायों को प्रयोग में ला रहे हैं। चूंकि कोरोना के साथ देश में ब्लैक और व्हाइट फंगस के मामले भी बढ़ रहे है, ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम उन चीज़ों का सेवन करें जो इन दोनों संक्रमणों से हमें सुरक्षा दे सकें। ऐसे ही कुछ विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों के बारे में जाने।

**नींबू :** नींबू को विटामिन सी और एंटीऑक्सिडेंट का अच्छा स्रोत माना जाता है। कोरोना और फंगल संक्रमण के समय में जब लोग अपनी इम्यूनिटी को मज़बूत करने की कोशिश में लगे हैं उनके लिए नींबू का सेवन सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट शरीर से फ्री रेडिकल्स को हटाने में सहायक है जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाकर संक्रमण का कारण बन सकती है। नींबू में थियामिन, राइबोफ्लोविन, विटामिन बी-6, पैंटोथेनिक एसिड, कॉपर और मैंगनीज भी अच्छी मात्रा में पाई जाती है।

**संतरा :** संतरे को विटामिन सी का बेहतर स्रोत माना जाता है। आहार विशेषज्ञों के अनुसार 1 मध्यम आकार के संतरे (100 ग्राम) में विटामिन सी की मात्रा 53.2 मिलीग्राम के करीब होती है। साइट्रिक युक्त फलों में पाए जाने वाले एंटीऑक्सिडेंट गुण हमारी इम्युनिटी को बढ़ाने के साथ फ्री रेडिकल्स के कारण हमारी कोशिकाओं को होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं।

**शिमला मिर्च :** खट्टे और साइट्रिक युक्त फलों की तरह शिमला मिर्च में भी विटामिन सी की समान मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा यह बीटा कैरोटीन से भी समृद्ध मानी जाती है। शिमला मिर्च में मौजूद खनिज और विटामिन, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मज़बूत करने के साथ, त्वचा की रंगत में सुधार करने और आंखों को स्वस्थ रखने में भी मददगार है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करने वाले ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस को भी कम करती है।

**आँवला :** आयुर्वेदिक चिकित्सा में सदियों से आंवले का इस्तेमाल विभिन्न रोगों के इलाज के लिए किया जाता रहा है। संतरे की तुलना में केवल एक आंवले में विटामिन सी की मात्रा लगभग 20 गुना अधिक होती है। विटामिन-सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट के रूप में कार्य करता है जो कि तंत्रिका तंत्र, प्रतिरक्षा प्रणाली और त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा आंवले का सेवन मेटाबॉलिज़्म को ठीक रखने, हड्डियों के निर्माण, प्रजनन और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने में मददगार है। रोज़ाना सुबह आंवले के जूस का सेवन ज़रूर करना चाहिए।

**अनानास :** अनानास को सदियों से पाचन को मज़बूत करने के साथ और सूजन की समस्याओं के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस फल में विटामिन सी और मैगनीज की उच्च मात्रा मौजूद होती हैं इसके अलावा यह कैलोरी में कम होने के साथ डाइट्री फाइबर और ब्रोमलेन से समृद्ध माना जाता है। रोज़ाना अनानास का सेवन करने से वायरल और बैक्टीरियल दोनों संक्रमणों का ख़तरा कम हो सकता है। इन सब उपायों के साथ हमें कोरोना से सावधान रहना है, और सरकार द्वारा घोषित गाइड लाइन्स को फॉलो करना है, जैसे बार-बार हाथ धोना, उचित दूरी बनाकर रखना, और बिना घर से वजह बाहर नहीं निकलना आदि।

## शेष.... प्रथम पृष्ठ

तो सरकार ने कहा कि सिर्फ मरे हैं। आपदा में अवसर तलाशती वह कंपनियां वेंटिलेटर बनाकर सप्लाई कर आई, जिन्हें इसका अनुभव ही नहीं था। नतीजतन 65 प्रतिशत ख़राब वेंटिलेटर की आपूर्ति हुई। पीएम केयर फंड से इसका भुगतान भी हो गया। जिन्हें ऑक्सीजन प्लांट लगाने का ठेका दिया, वे कंपनियां लापता हो गई। लाखों लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर गये। शर्मनाक हालात तो तब हुए जब कोरोना काल के दौरान पेट्रोलियम के दाम 21 रुपये प्रति लीटर बढ़ा संरक्षण मिलने के कारण खाने-पीने के सामान की कीमत 100 से 200 प्रतिशत तक बढ़ गई है। जहां किसानों के खेत में फल और सब्ज़ियां सड़ रही है, वहीं मंडी में इनके दाम दोगुने हो गये हैं। मौक़ापरस्त धंधेबाजों ने कोरोना काल को आपदा में अवसर माना है, जबकि सेवा भाव वाले लोग ऐसे समय में मानवता के लिए अपना सबकुछ न्यौछावर कर रहे हैं। जहां युवा कांग्रेस अध्यक्ष बी.वी. श्रीनिवास बग़ैर किसी भेदभाव के मरीज़ों की जान बचाने में लगे हैं, वहीं भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या मुस्लिम युवाओं को नौकरी से निकलवाकर एजेंडा सेट करने में। हम मानव बनें और मानवता को धारण करें। दूसरों के कष्टों को अपना कष्ट समझकर सहायता करें। कोरोना काल में जो देखने को मिल रहा है, वह दुखद है। मानवता को अपनाने के बजाय अधिकतर लोग और सत्ता के अवसर खोजते मौक़ापरस्त बन रहे हैं। वे अपने लाभ के लिए न सिर्फ कफ़न चोरी कर रहे हैं बल्कि लोगों को कफ़न उढ़ाने के लिए विवश कर रहे हैं। सत्ता भी उसी दिशा में ढकेल रही है। ऐसे में गुरुद्वारे, चर्च और मस्जिदों सहित कुछ मंदिर भी सेवा के लिए आगे आये हैं मगर जिन्हें सबसे आगे होना चाहिए, वो सबसे पीछे खड़े हैं। धर्म की राजनीति करने वाले ही अपने धर्म से नहीं सीख रहे, तो दूसरों से क्या उम्मीद की जाएं। ❑❑

## शेष.... पंजाब में अकाली दल....

है, उसे मैं उठापटक नहीं, बंटवारे की लड़ाई मानता हूं। वहां लड़ाई इस बात की है कि तुमको ज़्यादा मिल गया, मुझे नहीं मिला। पांच वर्ष किया कुछ नहीं। अब चुनाव सिर पर है तो जनता को जवाब दिया जाए, यह उन लोगों की समझ में नहीं आ रहा इसलिए आपस में ही एक दूसरें का कुर्ता फाड़ने में लग गए हैं। हमें इससे कोई लेना-देना नहीं है। हम नशामुक्त और खुशहाल पंजाब के वादे के साथ चुनाव में जाएंगे।

**प्रश्न:-** असम में भाजपा ने कांग्रेस से हिमंत बिस्व सरमा को लिया था, बंगाल के चुनाव में टीएमसी से शुभेन्दु अधिकारी को ले लिया, पंजाब में भी क्या ऐसे कुछ नेताओं पर आपकी नज़र है.?

**उत्तर:-** भाजपा की नीतियों और नेतृत्व के प्रति जिनका भी विश्वास है, उन सभी का भाजपा में स्वागत है। हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, इसमें आने के लिए किसी पर भी पाबंदियां नहीं हैं।

**प्रश्न:-** नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में खुद को सहज नहीं पा रहे हैं, उनके लिए पार्टी के दरवाज़े खुले हैं या नहीं?

**उत्तर:-** ऐसे लोगों को पार्टी में वापस लेना है नहीं लेना है, यह फैसला किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा। इसके लिए हमारा नेतृत्व सामूहिक विचार विमर्श के बाद फैसला लेगा।

**प्रश्न:-** किसान आंदोलन का क्या असर पंजाब चुनाव पर पड़ता देखते हैं, विशेषकर भाजपा के संदर्भ में..?

**उत्तर:-** किसानों के हक़ में जितने फैसले नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने लिए है, उतने तो शायद पूर्ववर्ती किसी भी सरकार ने नही लिए। रही बात किसान आंदोलन की तो मुझे तो नहीं लगता कि कहीं किसान आंदोलित भी हैं। बस कुछ नेता है जो किसानों के नाम पर अपनी राजनीति चमकाए रखना चाहते हैं। ❑❑

## शेष.... नए शिक्षा मॉडल के दूरगामी प्रभाव

बाद भी चौदह वर्ष तक की आयु के महज़ 12.4 प्रतिशत विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में प्रवेश पा रहे हैं। संसाधन,रोजगारपक शिक्षा का अभाव आज भी इस तंत्र को झेलना पड़ता है।

आधुनिक शिक्षा में तेज़ी लाने के लिए एक मज़बत निगरानी तंत्र की भी दरकार है, ताकि काम निर्बाध गति से हों। साथ ही कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति ई-लर्निंग कार्यक्रम को सुगमता से आगे बढ़ाया जा सकेगा। इसके लिए ज़मीनी स्तर पर एक व्यापक, दूरदर्शी और प्रभावी ख़ाका तैयार करना होगा, जिससे डिजिटलीकरण की राह को सुदूर इलाकों में आसान बनाया जा सके। इस मुहिम को एक आंदोलन का रूप दिए बग़ैर स्कूलों को स्मार्ट स्कूल की दिशा में आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा। ❑❑

## शेष.... ज़हरीला होता भूजल....

के पानी को साफ कर क्या सबको शुद्ध पानी उपलबध कराया जा सकता है? भूजल के विषैले होने और भूजल का स्तर लगातार नीचे जैसी विकट समस्या के समाधान के बग़ैर देश के प्रत्येक परिवार को कैसे साफ और शुद्ध जल उपलब्ध कराया जा सकता है? जल संचयन, बड़े पैमाने पर जल शोधन और जल का अपरिग्रह करके जल से ताल्लुक़ रखने वाली सभी तरह की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ❑❑

## शेष.... अफ़ग़ानिस्तान में शान्ति दूर की कौड़ी

और आईएसआइ के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाक़ात की। दरअसल पाकिस्तान हुक्मरान किसी भी कीमत पर काबुल को नियंत्रित करने का सुनहरी मौक़े को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। बीच-बीच में तालिबान कमांडर अपने रूसी और ईरानी संपर्कों से भी सलाह ले रहे हैं और इसका नतीजा भी सामने आता रहा है। अब न तो तालिबान को अमेरिका पर कोई भरोसा रह गया है, न ही अमेरिका को तालिबान पर। अमेरिकी प्रशासन तालिबान को शक की निगाह से देख रहा है क्योंकि तालिबान अभी भी अलक़ायदा के संपर्क में है हालांकि तालिबान के वरिष्ठ कमांडरों ने अपने लोगों को आदेश जारी कर रखा है कि वे विदेशी आतंकियों को शरण न दें। लेकिन ज़मीन पर इस आदेश को नहीं मान तालिबान भीतर ही भीतर नई रणनीति तैयार करने में लगा है।

दोहा शान्ति वार्ता में पाकिस्तान की भूमिका को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। अफ़ग़ानिस्तान को लेकर पाकिस्तान का नज़रिया एकदम साफ और स्पष्ट है। पाकिस्तानी सेना और आइएसआइ का तर्क है कि अफ़ग़ानिस्तान उसका सबसे करीबी पड़ोसी है, इसलिए वह आर्थिक, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, चूंकि अफ़ग़ानिस्तान की सबसे मज़बूत जनजाति पश्तूनों का पाकिस्तान में रहने वाले पश्तूनों के साथ रोटी-बोटी का रिश्ता है, इसलिए पाकिस्तान किसी भी क़ीमत पर काबुल में अपने हितों की कुर्बानी नहीं दे सकता। पश्तूनों की बड़ी आबादी पाकिस्तान के ख़ैबर पख़्तूनख़्वां प्रांत में है। ऐसे में क़ाबुल में पाकिस्तान समर्थक सरकार का होना उसके हित में होगा।

पाकिस्तान हुक्मरान अमेरिकी कूटनीति को हमेशा शक की नज़रों से देखते रहे हैं। संभवत इसलिए समय समय पर वे अफ़ग़ानिस्तान से जुड़े मामलों में अमेरिका को झटका भी देते रहे हैं। आइएसआइ के अधिकारियों का तर्क है कि अमेरिका का आज जो दुश्मन है, वह कल अमेरिका का दोस्त हो सकता है। अफ़ग़ानिस्तान से लेकर पश्चिम एशिया तक की अमेरिकी कूटनीति पर अमेरिकी डीप स्टेट (एक समूह हो गुप्त रूप से राज्य की नीतियों को प्रभावित करता है, चाहे सत्ता पर कोई भी दल काबिज़ हो) कब्ज़ा है। डेमोक्रेट हों या रिपब्लिकन, अफ़ग़ानिस्तान से लेकर पश्चिम एशिया तक के मामलों में दोनों एक ही नीति अपनाते हैं। बेशक दोनों की भाषा और शब्दों का चयन बदलता रहता है, लेकिन उनकी कूटनीति में कोई फर्क नहीं होता। पाकिस्तान सत्ता प्रतिष्ठान का तर्क है कि बराक ओबामा की भाषा तो नरम थी, लेकिन उनके सहयोगियों की भाषा अफ़ग़ानिस्तान को लेकर धमकाने वाली रही। वे अक्सर पाकिस्तान को धमकाने वाले अंदाज़ में बात करते थे। उनका तर्क है कि अमेरिकी सत्ता इस इलाके के देशों को आपस मे लड़ाने के खेल में ही विश्वास करती आई है, ताकि इस पूरे क्षेत्र में अमेरिकी हित सधते रहें। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकाल में स्थिति बदली। ट्रम्प खुद ही धमकाने वाले भाषा का इस्तेमाल करने लगे। दरअसल, अफ़ग़ानिस्तान में पाकिस्तान के अपने स्वतंत्र हित हैं। यही कारण है कि अफ़ग़ानिस्तान में वह अपना खेल अमेरिकी प्रभाव से बाहर निकल कर करता है। पाकिस्तान वैसे तो अफ़ग़ान शान्ति वार्ता में अमेरिका की मदद करने का दावा करता रहा है, लेकिन वह पूरी तरह से अमेरिका के इशारे पर चल रहा है, यह कहना ग़लत होगा।

निश्चित तौर पर दोहा में चल रही शान्ति वार्ता को लेकर अभी भी असमंजस है। बाइडेन प्रशासन क्या अफ़ग़ानिस्तान की धरती से पूरी तरह से अपनी सेना हटा लेगा, इसको लेकर अभी भी प्रश्न उठ रहे हैं। क्या तालिबान के वर्चस्व को उत्तरी अफ़ग़ानिस्तान में मज़बूत उज्बेक और ताजिक पूरी तरह से काबुल पर कब्ज़ा करके बैठ जाए? क्योंकि इस इलाके की भू-राजनीति में पाकिस्तान की मज़बूती ईरान स्वीकार करने को आज भी तैयार नहीं है। ऐसे हालात में अफ़ग़ानिस्तान में शान्ति अभी दूर की कौड़ी है। ❑❑

## शेष.... मोदीराज के 7 साल, किसान के 7 सवाल

डीजल, पेट्रोल के दाम में इतनी बढ़ोत्तरी क्यों हुई? इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार को दोष देना गलत है। मई 2014 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बच्चे तेल का दाम 106 डॉलर प्रति बैरल था और दिल्ली में डीजल 55 रुपए लीटर मिलता था। आज कच्चा तेल 67 रुपये प्रति बैरल मिल रहा है जबकि डीजल का दाम सौ के आसपास घूम रहा है। इसी सरकार के कार्यकाल में यूरिया की भारी किल्लत हुई और डी.ए.पी. तथा पोटाश के दाम बेतहाशा बढ़े।

**छह :** सरकार ने किसान को बर्बाद करने वाली इंपोर्ट-एक्सपोर्ट नीति क्यों अपनाई? कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के बजाय सरकार ने आलू और प्याज़ के निर्यात पर पाबंदी लगाई। अरहर और चने की दाल के आयात को खुली छूट दी गई जिससे मंडी में हमारे अपने किसानों को फसल का दाम नहीं मिला।

**सातवां :** जिन तीन क़ानूनों को किसान ने कभी मांगा नहीं, चाहा नहीं, उन्हें किसान से बिना पूछे उन पर क्यों थोप दिया गया। पराली के क़ानून में किसान पर एक करोड़ रुपए तक जुर्माना और पांच वर्ष की सज़ा का प्रावधान क्यों बनाया गया? बिजली क़ानून के ड्राफ्ट में किसान की सस्ती बिजली पर हमला क्यों? किसानों के ऐतिहासिक आंदोलन के बाद भी सरकार ने कान बंद क्यों कर रखे हैं? आज किसान इन सवालों का जवाब मांग रहे हैं। 'नरेन्द्र मोदी किसान विरोधी' जैसे नारे किसान के मूड का इशारा करते हैं। इस सरकार को काले झंडे दिखाने का यह मतलब क़तई नहीं है कि किसान इससे पिछली सरकारों के मुरीद हैं। वह जानते हैं कि इस देश की कोई भी केन्द्र सरकार किसान हितैषी कहलाने की हक़दार नहीं है। ❑❑

## शेष.... मंज़र पस-मंज़र

अंजाम दिया। 24 मई को हिसार में पत्नी के अवैध संबंधों के शक में एक व्यक्ति ने उसके प्रेमी के 9 वर्षीय बेटे को नहर में फेंक कर मार डाला। 24 मई को हिसार में बलात्कार की 03 घटनाएं दर्ज की गई। 24 मई को यमुना नगर में एक महिला से 05 व्यक्तियों ने बलात्कार किया। 25 मई को यमुना नगर ही में विवाह का झांसा देकर एक महिला से बलात्कार करने का मामला सामने आया। 26 मई को पलवल के मुंडकटी थाना क्षेत्र के गांव में एक युवक ने 6 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर उससे रेप करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। 27 मई को पानीपत में एक महिला द्वारा ख़र्च के लिए अपने पति से पैसे मांगने से गुस्साए पति तथा महिला की ननद और ननदोई सहित 6 लोगों ने उसे तवे से बुरी तरह पीटने के बाद कमरे में बंद कर दिया। 27 मई को भिवानी जिले में एक युवक की खेतों में हत्या कर दी गई। अपराधियों के बेख़ौफ होने का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि 27 मई को रोहतक के गांव इन्द्रगढ़ में अवैध शराब पकड़ने गई सी.एम. फ्लाइंग और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम पर एक महिला समेत तस्करों के गिरोह ने हमला कर दिया और एक कर्मचारी के गले की चैन तक छीन ली तथा सरकारी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। हरियाणा की क़ानून व्यवस्था की स्थिति का हाल इस घटना से भी लगा सकते हैं कि 29 मई को कैथल के 'थेह नेवल' में चौपाल की दीवार उखाड़ने को लेकर 2 गुटों का झगड़ा सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर झगड़ रहे लोगों ने ही हमला करके पुलिस पर ईंटें बरसाईं और पी.सी.आर. गाड़ी के शीशें तक तोड़ डाले।

हरियाणा में आपराधिक वारदातें कितनी बढ़ चुकी है इसका अंदाज़ा इस उदाहरण से भी लगाया जा सकता है कि 29 मई को विभिन्न विवादों के चलते रंजिश के परिणामस्वरूप मात्र 12 घंटों के अंतराल में रोहतक के गांवों सांघी, माजरा तथा बहुअकबरपुर में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। 2 घटनाओं में आरोपियों ने हत्याओं में चाकू और एक घटना में फरसे का इस्तेमाल किया।

हालांकि हरियाणा पुलिस अपने काम के प्रति समर्पित है। यह उक्त 2 सप्ताह की घटनाओं से ही स्पष्ट है कि हरियाणा में अपराध का ग्राफ कहां पहुंच चुका है, सरकार को इसे रोकने के लिए प्रभावी क़दम उठाने चाहिए ताकि लोगों में असुरक्षा की भावना दूर हो सके। ❑❑

SHANTI MISSION (HINDI WEEKLY) NEW DELHI Postal Registration No. DL(C)-01/1266/2021-23
Publishing Date : 30 May.2021 Posting Days : MON. - TUE. at N.D.P.S.O. New Delhi-110002 R.N.I. 57270/93

मंज़र पस-मंज़र — मीम.सीन.जीम

# •मनमानी पर लगाम•ख़तरे पर असमंजस

# हरियाणा में बढ़ता अपराध

## मनमानी पर लगाम

काफी जद्दोजहद के बाद फेसबुक ने यह साफ कर दिया है कि वह भारत के सूचना तकनीक नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करेगा। हालांकि इसके साथ ही फेसबुक की ओर से यह भी कहा गया है कि सरकार के साथ उन मुद्दों पर विचार जारी रहेगा, जिन पर अधिक संपर्क रखने की ज़रूरत है। इससे पहले सरकार और टेलिकॉम कंपनियों के सुर अलग-अलग है।

फेसबुक, इंस्टाग्राम और टवीटर सरीखे सूचना-संवाद एवं अभिव्यक्ति के डिजिटल प्लेटफार्म चलाने वाली कंपनियां भारत में किस तरह मनमानी करने पर आमादा हैं, इसका उदाहरण है कि उनकी ओर से सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने से इंकार करना। इन दिशा-निर्देशों के तहत इन कंपनियों को आपत्तिजनक सामग्री हटाने, शिकायत निवारण की व्यवस्था बनाने और सक्षम अधिकारियों के नाम-पते देने को कहा गया था। स्थिति यह है कि सी भी कंपनी ने किसी निद्रेश का पालन करने की ज़रूरत नहीं समझी। यह देश के शासन और उसके नियम क़ानूनों की खुली अनदेखी का प्रमाण ही है कि ये कंपनियां शिकायतों के निपटारे के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करने तक को तैयार नहीं क़ायदे से (डेड लाइन 25 मई) तक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि डिजिटल प्लेटफाम्र चलाने वाली कंपनियां टकराव के मूड में हैं। इसका संकेत इससे मिलता है कि उन्होंने यह बताने की भी ज़हमत नहीं उठाई कि वे ऐसा क्यों नहीं कर सकती हैं? उनके पास ले-देकर यही बहाना है कि वे अमेरिका स्थित अपने मुख्यालयों के निर्देश की प्रतीक्षा कर रही हैं। यह भारत सरकार की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि ये कंपनियां यूरोपीय देशों के समक्ष न केवल नतमस्तक हो जाती है, बल्कि उनके क़ानूनों के हिसाब से संचालित भी होती है।

इसका कोई औचित्य नहीं कि कोई विदेशी कंपनी भारत में काम करे, लेकिन भारतीय क़ानूनों का पालन करने से इंकार करे। यह एक किस्म की दादागिरी है और इसका सख़्त जवाब दिया जाना चाहिए इसलिए और भी, क्योंकि इंटरनेट मीडिया कंपनियों की मनमानी बढ़ती जा रही है। बतौर उदाहरण फेसबुक, वाट्सऐप के लिए भारत में निजता संबंधी उस नीति पर अमल नहीं करना चाहता, जिसे वह यूरोपीय देशों में इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह टवीटर बेशर्मी के साथ दोहरे मानदंडों पर चल रहा है। इसका ताजा उदाहरण टूलकिट विवाद में भाजपा नेता सांबित पात्रा के एक टवीट को इस रूप से चिह्नित करना है कि उसमें तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया। इस मामले की जांच पुलिस कर रही है और अभी यह साफ नहीं कि उक्त टूलकिट किसकी शरारत है, लेकिन टवीटर फौरन इस नतीजे पर पहुंच गया कि सांबित पात्रा की ओर से किए गए टवीट में तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है, क्या टवीटर एक डिजिटल प्लेटफार्म के साथ पुलिस और न्यायाधीश भी है? यदि नहीं तो उसने कैसे जान लिया कि उक्त टवीट के तथ्यों की अनदेखी हुई है? प्रश्न यह भी है कि क्या वह सभी टवीट के तथ्य जांचता है?

## ख़तरे पर असमंजस

अचानक यह ख़बर आना राहत की बात है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए ख़तरनाक नहीं होगी। दरअसल, जब से इस बारे में चेतावनियां आने लगीं, तब से ही राज्यों से लेकर अभिभावकों तक की नींद उड़ी हुई है। ऐसा होना लाज़िमी भी है। बच्चों के साथ स्थितियां गंभीर रूप धारण करते देर भी नहीं लगती। दूसरी लहर का क़हर तो हम भुगत ही रहे हैं। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि हालात इतने बदतर हो जाएंगे। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा का मामला और गंभीर हो जाता है। पर अब नए तथ्य सामने आए है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस आशंका को बेबुनियाद बताया है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए ज़्यादा घातक होगी। कारण यह कि इस बारे में कोई ठोस वैज्ञानिक संकेत नहीं मिले। जबकि कुछ दिन पहले ही केन्द्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाक़ायदा चेतावनी दी थी कि तीसरी लहर बच्चों के लिए सबसे ख़तरनाक होगी। यहां तक कहा गया था कि इसमें करीब पचास प्रतिशत मरीज़ बच्चे हो सकते हैं। ऐसी ही चेतावनियां देश-विदेश के महामारी विशेषज्ञ भी देते रहे। इन चेतावनियों के साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सतर्क करते हुए एहतियाती कदम उठाने को भी कहा था इसलिए ज़्यादातर राज्यों ने इस ख़तरे से निपटने की तैयारियां शुरू कर दीं। कुछ राज्यों ने बाल कोविड केन्द्र और विशेष कार्य बल आदि बना लिए हैं। महामारी के पूरे परिदृश्य को देखें तो विषाणु के नए-नए रूप ज़्यादा जानलेवा साबित हो रहे हैं। कुछ मिलाकर ऐसी जटिल स्थिति बन गई कि किसी को कुछ नहीं सूझ रहा। वैज्ञानिक और चिकित्सक ख़ुद हैरान हैं। कभी लग रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक होगी, कभी लग रहा है नहीं होगी। हालांकि ऐसा ख़तरा नहीं मानने का आधार पहली और दूसरी लहर के आंकड़े ही हैं। अभी तक बच्चों के संक्रमण के जो मामले आए भी, वे गंभीर नहीं थे। जबकि पिछले एक माह में बच्चों में संक्रमण के मामले कुछ तो बढ़े हैं। इनमें शिशुओं से लेकर किशोरवय तक के बच्चे हैं। एक और तर्क दिया जा रहा है। वह यह कि विषाणु जिस रिसेप्टर के ज़रिए कोशिका से जुड़ता है, वह बच्चों में कम होता है। इसलिए बच्चों को ज़्यादा ख़तरा नहीं होगा। वैसे यह विस्तृत अध्ययन और शोध के विषय हैं। इनमें लंबा समय लगता है। जब तक देश के हर जिले, तहसील और गांव तक से पूरे और सही आंकड़े नहीं मिलते, तक तक कोई विश्वसनीय निष्कर्ष निकाल पाना संभव नहीं है।

दरअसल महामारी के विस्फोट ने सबको हिला डाला है। बस जैसे तैसे मरीज़ों की जान बच जाए, यही कोशिश दिखती है। तीसरी लहर का क़हर कब और कैसा होगा, कोई नहीं जानता। विषाणु के स्वरूप से लेकर महामारी के इलाज तक पर चिकित्सक और वैज्ञानिक उलझन में हैं। प्रधानमंत्री ने विषाणु को बहरूपिया और धूर्त की संज्ञा दी है। पता नहीं किस रूप में कब और कहां हमला कर दे। ऐसी असमंजस की सूरत में रास्ता यही है कि कई मोर्चों पर तैयारी रखी जाए। लिहाज़ा हमें यह मान कर नहीं बैठ जाना चाहिए कि तीसरी लहर बच्चों के लिए कम घातक होगी। बल्कि यह मानते हुए कि अगले लहर और जानलेवा हो सकती है, राज्यों को युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियां जारी रखनी चाहिए।

## हरियाणा में बढ़ता अपराध

हरियाणा में दिन-दहाड़े, सरेआम गोलीबारी, हत्या, बलात्कार व अन्य अपराधों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। बीते मई में ही दर्जनों अपहरण और बलात्कार करने के मामले सामने आए हैं जिनमें, 14 मई को मानेसर में एक युवती का अपहरण और बलात्कार, 16 मई को जींद के गढ़ी थाना इलाके में एक व्यक्ति द्वारा सब्जी में नशीला पदार्थ खिला कर अपनी पुत्रवधु से बलात्कार। 18 मई को पलवल जिले में घर में सो रही 15 वर्षीय नाबालिग से 2 युवकों ने बंदूक की नोक पर बलात्कार कर फरार हो गए। 23 मई को फरीदाबाद में घरेलू नौकरानी का काम करने वाली युवती के साथ तीन लोगों ने बलात्कार की घटना को

बाक़ी पेज 11 पर

## कोरोना से ठीक होने के बाद भी बना रहता है ख़तरा : अध्ययन

ब्रिटेन के शेफील्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के मुताबिक, कोरोना से ठीक हो चुके मरीज़ों में फेफड़ों का ये नुकसान नियमित सीटी स्कैन और नैदानिक परीक्षणों (क्लीनिकल टेस्ट) में पता नहीं चला था और ऐसे में ज़ाहिर है कि मरीज़ों को बताया जाएगा कि उनके फेफड़ें सामान्य है, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इसकी जांच के लिए ही हाइपरपोलराइज्ड जीनन एमआरआई स्कैन की ज़रूरत पड़ी। दरअसल हाइपरपोलराइज्ड जीनन एमआरआई स्कैन से फेफड़ों के उन हिस्सों का पता लगाया जा रहा है, जहां फेफड़ों पर कोरोना वायरस के लम्बे समय तक प्रभाव के कारण ऑक्सीजन लेने की क्षमता प्रभावित हुई है, भले ही वो सीटी स्कैन में सामान्य देखते हैं। प्रमुख शोधकर्ता फेरगस ग्लीसन ने कहा कि कोरोना के कई मरीज़ों को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी कई महीनों तक सांस लेने में दिक्क़त महसूस होती है, जबकि सीटी स्कैन से पता चलता है कि उनके फेफड़े सामान्य रूप से ही काम कर रहे हैं, लेकिन जब हाइपरपोलराइज्ड जीनन एमआरआई स्कैन किया गया, तो पाया गया कि सीटी स्कैन में न दिखने वाली असामान्यता फेफड़ों के सभी हिस्सों में सामान्य रूप से ऑक्सीजन पहुंचने से रोकती है।

ज़रूरी ऐलान

आपकी ख़रीदारी अवधि पते की चिट पर अंकित है। अवधि की समाप्ति से पूर्व रक़म भेजने की कृपा करें।

रक़म भेजने के तरीक़े:-
❶ मनीआर्डर द्वारा ❷ Paytm या PhonePe द्वारा 9811198820 पर SHANTI MISSION
❸ ऑनलाइन हेतु बैंक खाते का विवरण
SBI A/c 10310541455
Branch: Indraprastha Estate
IFS Code: SBIN0001187

अपने प्रिय अख़बार साप्ताहिक शांति मिशन को इंटरनेट पर देखने के लिये लॉगऑन करें:
www.aljamiat.in —— www.jahazimedia.com
Mob. 9811198820 — E-mail: Shantimissionweekly@gmail.com

ख़रीदारी चन्दा

| | |
|---|---|
| वार्षिक | Rs.130/- |
| 6 महीने के लिए | Rs.70/- |
| एक प्रति | Rs.3/- |

जानकारी के लिये सम्पर्क करें
साप्ताहिक
शांति मिशन
1, बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23311455

जमीअत ट्रस्ट सोसायटी की तरफ से मुद्रक, प्रकाशक शकील अहमद सैयद ने शेरवानी आर्ट प्रिंटर्स, 1480, क़ासिमजान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवाकर मदनी हाल, न. 1, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित किया। संपादक:- मोहम्मद सालिम, फोन:- 23311455, 23317729, फैक्स:- 23316173